राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 20 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-293 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बांग्लादेश में 2 न्यूज चैनल्स, अवामी लीग के ऑफिस फूंके

■ शेख हसीना विरोधी नेता की मौत के बाद हिंसा, हिंदू युवक को जलाया

एजेंसी

ढाका। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हिंसा भड़क गई है। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई है और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया गया है। उस्मान हादी शेख हसीना के खिलाफ जुलाई 2024 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान सिर में गोली मारी गई थी। इसके बाद उन्हें बेहतर उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया था। 6 दिन बाद उनकी मौत हो गई। बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक को पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद उसके शव को नग्न करके एक पेड़ से लटका कर आग लगा दी। पुलिस ने मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में की है पुलिस ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात भालुका में हुई।

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से सटे एयरबेस पर होंगे अपाचे हेलिकॉप्टर तैनात

■ जैसलमेर में हुए 2 युद्धाभ्यास में थे शामिल

एजेंसी

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलिकॉप्टर कहे जाने वाले AH-64E अपाचे अटैक हेलिकॉप्टरों को जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया है, जो एक समय में 256 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 16 लक्ष्यों को प्राथमिकता दे सकता है। ये हेलिकॉप्टर अब पाकिस्तान सीमा की निगरानी और भारत की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत बनाएंगे। हाल ही में जैसलमेर क्षेत्र में हुए सैन्य अभ्यास त्रिशूल और मरु ज्वाला में इन हेलिकॉप्टरों का उपयोग किया गया था। अभ्यास के बाद इन्हें पश्चिमी सीमा के पास एक महत्वपूर्ण एयरबेस पर तैनात किया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय थल सेना के अपाचे हेलिकॉप्टरों ने किसी बड़े सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान इन हेलिकॉप्टरों ने तय लक्ष्यों पर सटीक हमला किया। जून 2025 में अमेरिका से मिले 3 अपाचे हेलिकॉप्टरों की पहली खेप की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। ये हेलिकॉप्टर अब ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए तैयार हैं। राजस्थान में स्क्वाड्रन होने की वजह से इनका रंग रेत (मिट्टी) जैसा रखा गया है, जिससे रेगिस्तानी इलाकों में छुपने में मदद मिलती है।

दिल्ली-पंजाब समेत कई राज्यों में ईडी की छापेमारी

करोड़ों रुपये और 300 किलो चांदी जब्त

एजेंसी

नई दिल्ली। डंकी रूट के जरिए भारत से युवाओं को अमेरिका भेजने के मामले में ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली-पंजाब समेत कई राज्यों में दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी ने चार करोड़ रुपये से ज्यादा नकद और 300 किलो से ज्यादा चांदी और छह किलो सोने के बिस्किट जब्त किए। ये छापे गुरुवार को दिल्ली, पंजाब (जालंधर) और हरियाणा (पानीपत) में एक दर्जन से ज्यादा जगहों पर मारे गए।अधिकारियों ने दावा किया कि दिल्ली के एक ट्रैवल एजेंट के ठिकाने से 4.62 करोड़ रुपये कैश, 313 किलो चांदी और 6 किलो सोने के बिस्किट जब्त किए हैं। जांचकताओं ने छापों के दौरान मिले फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ आपत्तिजनक चैट भी बरामद की हैं। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा में एक मुख्य आरोपी के ठिकाने से 'डंकी' बिजनेस से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेज मिले हैं। आरोप है कि एजेंट अवैध रूप से अमेरिका जाने वाले लोगों के प्रॉपर्टी के दस्तावेज अपने कमीशन की रकम की गारंटी के तौर पर रखते थे। 'डंकी' शब्द का मतलब उस लंबी और मुश्किल यात्रा से है जो अप्रवासी अवैध रूप से देशों में घुसने के लिए करते हैं।केंद्रीय जांच एजेंसी ने जुलाई में डंकी मामले में पहली बार

छापेमारी की थी। हाल ही में कुछ ट्रैवल एजेंटों की 5 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी, जिन्होंने इस अवैध रैकेट के पीछे कुछ कथित आरोपियों की पहचान की गई। एऊ की जांच पंजाब और हरियाणा पुलिस द्वारा फरवरी 2025 में अमेरिकी सरकार द्वारा सैन्य कार्गो विमानों में 330 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजने के संबंध में दर्ज की गई। इन मामलों में कई एफआईआर हुई। ईडी का कहना है कि आरोपियों ने उन्होंने भोले-भाले लोगों को कानूनी रूप से अमेरिका भेजने का लालच देकर धोखा दिया और इसके लिए भारी रकम वसूली।हालांकि पैसे लेने के बावजूद लोगों को दक्षिण अमेरिकी देशों के रास्ते खतरनाक रास्तों से भेजा गया, सीमा पार करके अवैध रूप से अमेरिका में घुसने के लिए मजबूर किया गया। कुछ दिन पहले जारी ईडी के एक बयान के अनुसार, पूरी यात्रा के दौरान इन लोगों को टॉर्चर किया गया, उनसे और पैसे वसूले गए और उनसे गैर-कानूनी काम करवाए गए।

राजनाथ बोले: सुदर्शन चक्र से मजूबत होगी देश की सुरक्षा

ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहे सेना

एजेंसी

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली में आयोजित एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्क्लेव में गुरुवार को रक्षा मंत्री ने भाग लिया। उन्होंने वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से मिले रणनीतिक और ऑपरेशनल संबंधी सबक को ध्यान में रखकर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहें। रक्षा मंत्री ने वायुसेना को तकनीकी रूप से उन्नत, रणनीतिक रूप से आत्मविश्वासी और हर परिस्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया देने वाली फोर्स बताया। कॉन्क्लेव में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जब पाकिस्तान ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की असफल कोशिश की, तब आम लोग शांत रहे और

सामान्य गतिविधियां जारी रहीं। यह भारतीय जनता के अपनी सेनाओं पर भरोसे को दिखाता है। ऐसी स्थिति में लोगों का संयम देश की तैयारी और क्षमता पर विश्वास को दशार्ता है। रूस-यूक्रेन युद्ध, इजराइल-हमास संघर्ष, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से स्पष्ट है कि आधुनिक युद्ध में एयर पावर केवल सामरिक नहीं, बल्कि रणनीतिक साधन बन चुकी है। इसकी ताकत गति, आश्चर्य और त्वरित प्रभाव में है, जिससे राजनीतिक नेतृत्व को भी स्पष्ट संदेश देने में मदद मिलती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित ह्यसुदर्शन चक्रह्ल को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। यह सिस्टम भारत की लेयर्ड एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करेगा। इसमें सेंसर, हथियार प्लेटफॉर्म और कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम का एकीकरण होगा, ताकि हवाई खतरों पर समय पर प्रतिक्रिया दी जा सके। युद्ध का स्वरूप अब तकनीक और नवाचार पर आधारित है। साइबर युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सैटेलाइट निगरानी और स्पेस टेक्नोलॉजी इसकी अहम कड़ियां हैं। ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के संयुक्त संचालन का उदाहरण है। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय पर जोर दिया। देश की राजधानी दिल्ली चौतरफा सुरक्षा सिस्टम से लैस होने जा रही है। इसे कैपिटल डोम नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने दिल्ली पर मिसाइलें दागी थीं, लेकिन हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही मार गिराया था। इसी के बाद दिल्ली को अलग से एक ह्यसुदर्शन चक्रह्ल का सुरक्षा घेरा देने पर मंथन किया गया। फिलहाल यह सिस्टम लगभग तैयार है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की अगुवाई में जिस डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है, उसमें दिल्ली के चारों ओर तीन सुरक्षा घेरे होंगे।

दिल्ली में लगातार छठे दिन हवा जहरीली, एक्यूआई 387

■ धुंध-कोहरे के कारण शुक्रवार को 152 फ्लाइट्स कैंसिल

एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली में गुरुवार से प्रदूषण के खिलाफ सख्त नियम लागू हो गए। इसके बावजूद शुक्रवार को लगातार छठे दिन हवा बेहद खराब रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, सुबह करीब 8 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी (AQI) 387 दर्ज किया गया। शहर में हवा की गुणवत्ता गुरुवार की तुलना में और भी बिगड़ गई है। कल शाम 4 बजे शहर का अदक 373 था। प्रदूषण के साथ शहर के ज्यादातर हिस्से जहरीले धुंध (स्मॉग) की चपेट में हैं। आईटीओ, गाजीपुर, पालम और ग्रेटर नोएडा के आसपास के इलाके भी धुंध की मोटी परत से घिरे रहे। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर आज दिन भर के लिए 152 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार, कैंसिल होने वाली फ्लाइट्स में 79 दिल्ली से जाने और 73 आने वाली फ्लाइट्स हैं। इनमें 4 इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल हैं। कई उड़ानें घंटों देरी से चल रही हैं। एअर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी कई एयरलाइनों ने उड़ानें प्रभावित होने की आशंका को लेकर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले गुरुवार को धुंध के कारण एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रह गई। इसके चलते 27 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। 100 से अधिक विमान देरी से उड़े। 80 से अधिक ट्रेन लेट हो गईं। दिल्ली में गुरुवार से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा फेज लागू हो गया। इसके तहत दिल्ली में सिर्फ इर-6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है।

तमिलनाडु-गुजरात में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, बंगाल में 58 लाख नाम कटे

एजेंसी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग शुक्रवार को तमिलनाडु और गुजरात में कराए गए स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR, सामान्य शब्दों में वोटर वेरिफिकेशन) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसके बाद मतदाता लिस्ट में अपने नाम चेक कर सकेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर को SIR की घोषणा के समय इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों

में 13.35 करोड़ मतदाता थे। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या घटकर 12.33 करोड़ रह गई है। यानी 1.02 करोड़ नाम हटाए गए हैं। बंगाल में 58 लाख 20 हजार 898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिह्नित किए गए हैं। राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85 हजार वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाता तय समय में नाम जोड़ने, सुधार करने और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। SIR का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। पश्चिम बंगाल- यहां 58 लाख 20 हजार 898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनमें 24 लाख 16 हजार 852 नाम मृत वोटरों के हैं। 19 लाख 88 हजार 76 वोटर ऐसे हैं जो दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं। 12 लाख 20 हजार 38 वोटर लापता, 1 लाख 38 हजार 328 डुप्लीकेट या फर्जी और 57 हजार 604 नाम अन्य कारणों से हटाने के प्रस्ताव में हैं।

हिजाब विवाद, सीएम नीतीश कुमार को महबूबा की बेटी की धमकी

एजेंसी

नई दिल्ली। बिहार में महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जम्मू-कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती की बेटी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) नेता इल्तिजा मुफ्ती ने धमकी दी है। इल्तिजा ने श्रीनगर में कहा- आपको (नीतीश) कोई हक नहीं बनता कि आप हमारे नकाब या हिजाब को हाथ लगाए। अगली बार हमारे हिजाब को हाथ लगाया तो हम मुसलमान औरतें ऐसा सबक सिखाएंगी कि जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। PDP नेता ने कहा- नीतीश कुमार ने जो हरकत की, उसके

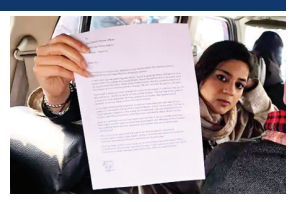

लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इल्तिजा ने कोठीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बिहार CM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि, पुलिस की ओर से इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है कि बिहार CM के खिलाफ FIR दर्ज की गई है या नहीं। बिहार CM नीतीश 15 दिसंबर को राजधानी पटना में एक समारोह में 1,283 आयुष डॉक्टरों को

संसद के शीतकालीन सत्र में 8 बिल पास

कांग्रेस का आरोप: शुरूआत टैगोर के और अंत महात्मा गांधी के अपमान से हुआ

एजेंसी

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को खत्म हुआ। 1 दिसंबर से शुरू हुआ सत्र 19 दिसंबर तक चला। केंद्र सरकार ने 14 बिल लाने की बात कही थी। विपक्ष का आरोप है कि 12 बिल ही पेश किए गए। दोनों सदनों से 8 बिल पास किए गए। 2 बिल कमेटी को भेजे गए। सरकार ने कुछ बिल पेश ही नहीं किए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया- सत्र की शुरूआत रवींद्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और अंत महात्मा गांधी के अपमान के साथ हुआ। पीएम मोदी की रणनीति साफ थी, जो आधुनिक भारत बनाने वाले तीन लोगों (टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू) का अपमान करना था। रमेश ने कहा- वंदे मातरम् पर बहस सरकार की नेहरू को बदनाम करने और इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने पर थी। 1937 में टैगोर की सिफारिश पर ही CWC ने फैसला किया था कि वंदे मातरम् के पहले दो छंदों को राष्ट्रगान के रूप में गाया जाएगा। MGNREGA की जगह G RAM G बिल लाना महात्मा गांधी का अपमान है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चला। इस दौरान राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 121% और लोकसभा की 111% रही।

राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने समापन भाषण में कहा- सत्र में जीरो आवर नोटिस (जरूरी मुद्दे सदन में उठाने की परमिशन मांगने का तरीका) की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा रही। हर दिन औसतन 84 नोटिस आए, जो पिछले सत्रों से 31% ज्यादा हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने पर संसद भवन में अपने चैंबर में पार्टियों के नेताओं और लोकसभा सांसदों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। सपा सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा ने VB-G RAM G बिल 2025 पर कहा, "भाजपा नाम बदलने में बहुत तेज है लेकिन नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। मनरेगा का नाम महात्मा गांधी के नाम से था और तमाम गरीब इस योजना का लाभ ले रहे थे। देश में महात्मा गांधी को मानने वाले लोग बड़ी संख्या में है। हम सभी लोग भगवान राम को भी मानते हैं लेकिन कहीं न कहीं भाजपा वोटों की राजनीति करने के लिए नाम बदल रही है।" भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया, अगले सत्र की कार्यवाही में शामिल होने से रोकने की मांग की। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। लेकिन वंदेमातरम के तुरंत बाद अध्यक्ष ने इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 111 प्रतिशत रही। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने VB-G RAM G बिल 2025 पर कहा- संसद का सत्र इतने दिनों से चल रहा है लेकिन आप आखिरी दिनों में कुछ बिल लेकर आते हैं और उसके लिए कम समय रखते हैं। उसे हड़बड़ी में पास करते हैं। ये अपने आप में संदिग्ध बात है। उन्होंने कहा- प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? चर्चा होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए।

चाय पर चर्चा: सत्र के समापन पर स्पीकर बिरला ने बुलाई

पीएम मोदी-प्रियंका समेत तमाम सांसद हुए शामिल

एजेंसी

नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र का आज समापन हो गया। अंतिम कार्यदिवस पर लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण कोई विधायी काम नहीं हुआ और स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का एलान कर दिया। थोड़ी देर बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने कक्ष में सांसदों को चाय पर आमंत्रित किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत विभिन्न दलों के नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि संसद सत्र के समापन पर

लोकसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के साथ बैठक करते हैं। मानसून सत्र के समापन पर भी ऐसी बैठक हुई थी, लेकिन विपक्ष ने उस बैठक का बहिष्कार किया था। इस बार की बैठक में प्रियंका गांधी शामिल हुईं। खास बात ये रही कि वायनाड से पहली बार की सांसद प्रियंका गांधी को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बगल वाली सीट दी गई। वहीं रक्षा मंत्री के पास वाली सीट पर प्रधानमंत्री मोदी बैठे दिखाई दिए। गुरुवार को लोकसभा में जब प्रियंका गांधी ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से समय नहीं मिलने की शिकायत की थी तो उन्होंने कहा था कि उनका दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है। गडकरी ने कहा कि आप प्रश्नकाल के बाद उनके ऑफिस में आकर मिल सकती हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कार्यालय में जाकर मुलाकात की थी, जहां गडकरी ने उन्हें स्वादिष्ट डिश भी खिलाई। सत्र समापन के बाद भी जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें भी सत्ता और विपक्षी सांसद मुस्कुराते हुए नजर आए, जो कहीं न कहीं देश के लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाती हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

मानव एकजुटता से ही बचेगा मानव- सभ्यता का अस्तित्व

संयुक्त राष्ट्र महासभा के सहस्राब्दी घोषणापत्र में एकजुटता को इक्कीसवीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूलभूत मूल्यों में से एक बताया गया है, जिसके अनुसार सबसे कम पीड़ित या सबसे कम लाभान्वित लोगों को सबसे अधिक लाभान्वित लोगों से सहायता मिलनी चाहिए। इसलिए, वैश्वीकरण और बढ़ती असमानता की चुनौती के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूत करना अपरिहार्य है। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा इस बात से आश्वस्त है कि गरीबी से लड़ने के लिए एकजुटता की संस्कृति और साझा करने की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।

(लेखक- ललित गर्ग)

(अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस -20 दिसंबर, 2025)

अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस हर साल 20 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2005 में घोषित किया था और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सतत विकास और विविधता में एकता को बढ़ावा देने के लिए लोगों को एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूक करना है, ताकि वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटा जा सके। इस दिवस को मनाते हुए मुख्य विचार है कि 'एकजुटता में नवाचार और प्रौद्योगिकी', 'युवा-नेतृत्व वाली एकजुटता' और 'सतत विकास लक्ष्यों के लिए एकजुटता' जैसे विषयों पर केंद्रित है। आज की दुनिया एक विचित्र और विरोधाभासी दौर से गुजर रही है। एक ओर विज्ञान, तकनीक और संचार ने पूरी पृथ्वी को एक छोटे से गाँव में बदल दिया है, तो दूसरी ओर मनुष्यों के बीच की दूरी, गरीबी, अशिक्षा, अविश्वास और वैमनस्य लगातार बढ़ता जा रहा है। युद्ध, आतंक, हिंसा, नस्लवाद, धार्मिक कट्टरता और आर्थिक असमानता ने मानव सभ्यता के मूल उद्देश्य पर ही प्रश्नचिह्न लगा दिया है। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता एवं एकजुटता दिवस न केवल नये मानवीय मूल्यों से प्रेरित समतामूलक समाज-संरचना की प्रेरणा है, बल्कि मानव जाति के लिए आत्ममंथन और आत्मसुधार का अवसर है। इस दिवस की मूल भावना यही है कि गरीबी का उन्मूलन हो, विकास अंतिम आदमी तक पहुंचे, मनुष्य पहले मनुष्य बने, उसके बाद उसकी पहचान राष्ट्र, धर्म, भाषा, रंग या विचारधारा से हो। आज जब दुनिया अनेक खेमों में बँटती जा रही है, तब 'सभी मानव पहले मानव' की चेतना को पुनः जाग्रत करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। भारतीय चिंतन ने सदियों पहले 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का जो सूत्र दिया था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, बल्कि यह भी है कि परिवार के हर सदस्य का सुख-दुःख, सम्मान और अस्तित्व समान रूप से महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक विश्व ने इस सूत्र को एक सुंदर नारे तक सीमित कर दिया है। व्यवहार में हम राष्ट्रहित, संप्रदायहित और व्यक्तिगत स्वार्थ को मानवहित से ऊपर रख देते हैं। परिणामस्वरूप युद्ध की आग में निर्दोष बच्चे झुलसते हैं, आतंक की छाया में सामान्य नागरिक भय के साथ जीने को मजबूर होते हैं और आर्थिक शोषण के कारण करोड़ों लोग अभाव और भूख की रेखा के नीचे जीवन बिताते हैं। मानव एकता का दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि जब तक मनुष्य की दृष्टि संकीर्ण रहेगी, तब तक शांति केवल एक सपना बनी रहेगी।

आज के युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जा रहे, वे विचारों, सूचनाओं और मानसिकताओं में भी लड़े जा रहे हैं। कहीं नस्ल के नाम पर घृणा फैलाई जा रही है, कहीं धर्म के नाम पर हिंसा को सही ठहराया जा रहा है, तो कहीं राष्ट्रवाद के उग्र स्वर मानवता की कोमल आवाज़ को दबा रहे हैं। आतंकवाद इसी विकृत मानसिकता का सबसे घातक रूप है, जो न धर्म को मानता है, न मानव मूल्यों को। ऐसे में शांति की बातें करना कई लोगों को आदर्शवादी या अव्यावहारिक लग सकता है, किंतु इतिहास साक्षी है कि हिंसा ने कभी स्थायी समाधान नहीं दिया। अस्तित्व की रक्षा केवल शांति, संवाद और सह-अस्तित्व से ही संभव है। मानव एकता दिवस इसी सत्य को वैश्विक चेतना में पुनः स्थापित करने का प्रयास है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के सहस्राब्दी घोषणापत्र में एकजुटता को इक्कीसवीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूलभूत मूल्यों में से एक बताया गया है, जिसके अनुसार सबसे कम पीड़ित या सबसे कम लाभान्वित लोगों को सबसे अधिक लाभान्वित लोगों से सहायता मिलनी चाहिए। इसलिए, वैश्वीकरण और बढ़ती असमानता की चुनौती के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को मजबूत करना अपरिहार्य है। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा इस बात से आश्वस्त है कि गरीबी से लड़ने के लिए एकजुटता की संस्कृति और साझा करने की भावना को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की घोषणा जैसी पहलों के माध्यम से, एकजुटता की अवधारणा को गरीबी के खिलाफ लड़ाई में और सभी संबंधित हितधारकों की भागीदारी में महत्वपूर्ण के रूप में बढ़ावा दिया गया।

मानव एकजुटता का अर्थ केवल संकट के समय सहायता करना नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में संवेदनशीलता, करुणा, समानता और सहानुभूति को अपनाना है। जब हम किसी दूसरे देश के युद्ध पीड़ितों को केवल समाचार की सुर्खी मानकर आगे बढ़ जाते हैं, तब हमारी मानवता कहीं न कहीं मर जाती है। जब शरणार्थियों को बोझ समझा जाता है और गरीब देशों की पीड़ा को अनदेखा किया जाता है, तब वैश्विक एकता का विचार खोखला प्रतीत होता है। मानव एकता का संदेश यह है कि किसी भी कोने में बहाया गया रक्त, पूरी मानवता को आहत करता है और कहीं भी बहाया गया आँसू, हमारी सामूहिक असफलता का प्रतीक है। यह दिवस हमें सिखाता है कि विविधता हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भाषाएँ अलग हों, पूजा-पद्धतियाँ अलग हों, पर मनुष्य की पीड़ा, उसकी आशा और उसका सपना हर जगह एक जैसा होता है।

हिंसा और युद्ध के इस दौर में शांति की भाषा बोलना साहस का कार्य है। शांति केवल हथियारों के मौन का नाम नहीं, बल्कि न्याय, समानता और सम्मान से उपजा हुआ विश्वास है। जब तक दुनिया में गहरी आर्थिक असमानता रहेगी, जब तक कुछ देशों का विकास दूसरों के शोषण पर आधारित रहेगा, तब तक वास्तविक मानव एकता संभव नहीं है। इसलिए मानव एकजुटता दिवस सामाजिक और आर्थिक न्याय की भी माँग करता है। यह याद दिलाता है कि संपन्नता का उद्देश्य केवल उपभोग नहीं, बल्कि साझेदारी है और शक्ति का उद्देश्य केवल प्रभुत्व नहीं, बल्कि संरक्षण है। आज आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा, मीडिया और राजनीति मानव एकता के मूल्यों को बढ़ावा दें। बच्चों को प्रारंभ से ही यह सिखाया जाए कि दूसरे का दर्द समझना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं में वैश्विक नागरिकता की भावना विकसित हो, जिसमें वे स्वयं को केवल किसी एक राष्ट्र का नहीं, बल्कि पूरी मानवता का उत्तरदायी सदस्य मानें। तकनीक का उपयोग नफरत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि संवाद और समझ बढ़ाने के लिए हो। तभी यह दिवस केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं रहेगा, बल्कि जीवन की एक जीवंत प्रेरणा बन सकेगा।

एकजुटता का अर्थ केवल सरकारी संबंध ही नहीं, बल्कि समस्त जन कल्याण भी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार और सामाजिक विकास संबंधी पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य एक ऐसी समतापूर्ण दुनिया का निर्माण करना है जहाँ सभी को विकास के अवसर प्राप्त हों। यह प्रतिबद्धता एकजुटता के आधारशिला के रूप में सार्वभौमिक प्रगति में गहरी आस्था को दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र की एकजुटता की अवधारणा ही उसके मिशन का आधार है। सामूहिक सुरक्षा एक ऐसा सिद्धांत है जो राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग को प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर इस बात पर ज़ोर देता है कि सदस्य देशों को सहयोग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। इससे राष्ट्र सशस्त्र संघर्ष या आतंकवाद जैसे किसी भी खतरे के खिलाफ एकजुट हो सकते हैं। वैश्विक चुनौतियों के परस्पर संबंध को पहचानते हुए, संयुक्त राष्ट्र गरीबी, भूख और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की वकालत करता है। एकजुटता साझेदारी के माध्यम से प्रकट होती है जो संसाधनों के बंटवारे को बढ़ावा देती है और प्रत्येक राष्ट्र के प्रयासों को मजबूत करती है। अंततः मानव एकता एवं एकजुटता दिवस हमें एक सरल लेकिन गहन सत्य की ओर लौटने का आह्वान करता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका मनुष्य होना है। यदि हम इस पहचान को बचा पाए, तो युद्ध, आतंक और हिंसा की अंधेरी रात अपने आप छँटने लगेगी। वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को व्यवहार में उतारकर ही हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहाँ अस्तित्व भय से नहीं, विश्वास से संचालित हो; जहाँ शक्ति हथियारों में नहीं, करुणा में निहित हो; और जहाँ भविष्य की पीढ़ियाँ हमें एक ऐसी मानवता के रूप में याद करें, जिसने विभाजन नहीं, बल्कि एकता को चुना।

संपादकीय

आप की खास जीत

आम तौर पर आम आदमी पार्टी को शहरी जनाधार वाली पार्टी के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन हालिया ग्रामीण निकाय चुनावों में उसकी जीत ने राजनीतिक विश्लेषकों को खूब चौंकाया है। पंजाब के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के परिणामों ने राजनीतिक वर्चस्व और उभरते मतभेदों की कहानी भी बयां की है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी यानी आप ने ग्रामीण निकाय चुनावों में शानदार सफलता को दर्ज करते हुए राज्यभर में बड़ी संख्या में सीटें जीती हैं। जिसने इस बात की पुष्टि की है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के शहरों में ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में भी लोकप्रियता का आधार रखती है। वहीं दूसरे शब्दों में कहें तो ग्रामीण मतदाताओं में पंजाब की सत्ता में लंबे समय तक भागीदारी निभाने वाले राजनीतिक दलों से मोहभंग का सिलसिला लगातार बना हुआ है। हालांकि, आप की इस सफलता के साथ कुछ ऐसे पहलू भी जुड़े हैं, जिन पर पार्टी और उसके नेताओं को गहन विचार करने की जरूरत होगी। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का मजबूत प्रदर्शन उसके शासन के मॉडल के लिये निरंतर समर्थन का संकेत दे रहा है। यह एक ऐसा परिणाम है जो साल 2027 के राज्य विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में आप के पक्ष में सकारात्मक परिदृश्य बना सकता है। इसके विपरीत विरोधाभास यह भी है कि कई जगह ऐसे उल्लेखनीय उदाहरण सामने आए हैं, जहां आम आदमी पार्टी अपने नेताओं के गढ़ों में लड़खड़ा गई है। आप के कई प्रमुख नेता अपने ही गांवों में जीत हासिल करने में विफल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, आप को इस पर मंथन करने की जरूरत है। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने बठिंडा और मुक्तसर जैसे कुछ इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ दर्शायी है। जो पार्टी के लिये हौसला बढ़ाने वाले संकेत कहे जा सकते हैं। दरअसल, शिअद के प्रदर्शन को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी यदि इस बढ़त को आगे भी कायम रख पाती है तो उसके संगठनात्मक पुनरुद्धार के लिये दीर्घकालिक परिणाम सामने आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन निराशाजनक ही कहा जाएगा। दरअसल, अब भी कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करने लिये संघर्ष करती प्रतीत हुई है। ये कांग्रेस के लिये चिंता की ही बात हो सकती है कि वह अपने पारंपरिक गढ़ों तक में अब भी कोई ठोस व दमदार चुनौती पेश करने में असफल ही रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनानी आरंभ की है। हालांकि, उसकी यह बढ़त सिर्फ मामूली ही कही जाएगी। बहरहाल, कह सकते हैं कि चुनाव परिणामों से उपजी तसवीर पंजाब में बदलते राजनीतिक परिदृश्य की ओर ही इशारा करती नजर आती है। वैसे एक हकीकत यह भी है कि किसी भी चुनाव के परिणाम चुनावी परिदृश्य का आंशिक दृष्टिकोण ही परिभाषित करते हैं। मतदाता जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी की नीतियों से काफी हद तक संतुष्ट ही दिखे हैं। इसके बावजूद स्थानीय निष्ठाएं और उम्मीदवार विशिष्ट कारक प्रमुखता से सामने आते हैं। इन स्थानीय ग्रामीण इकाइयों के चुनावों में आम आदमी पार्टी के नेताओं के गृह क्षेत्रों में मिली हार इस बात की भी याद दिलाती है कि किसी दल के लिये राजनीतिक पूंजी बेहद नाजुक ही होती है। यह भी कि ग्रामीण मतदाता स्थानीय नेतृत्व के प्रति उतने ही सजग और संवेदनशील होते हैं, जितना कि राज्य स्तरीय विचारों के प्रति। आगे चलकर, अगर आप को पंजाब में अपने जनादेश को बनाये रखना है और साथ ही उसका विस्तार करना चाहती है, तो उसे जमीनी स्तर पर नेतृत्व को मजबूत प्राथमिकता के आधार पर तैयार करना होगा। साथ ही उसे ग्रामीण मतदाताओं की विभिन्न चिंताओं का समाधान भी प्राथमिकता के आधार पर करना होगा।

वीबीजी राम जी विधेयक और नाम की राजनीति विकास बनाम विरासत की लोकसभा में बहस

(लेखक - कांतिलाल मांडोत)

लोकसभा में भारत गारंटी फ़ॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी विधेयक का ध्वनिमत से पारित होना केवल एक कानून का पास होना नहीं है बल्कि यह भारतीय राजनीति में विकास की दिशा और नाम की राजनीति को लेकर चली आ रही बहस का नया अध्याय भी है। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन का वातावरण अत्यंत गरम रहा। विपक्ष ने नारेबाजी की वेल में आकर कागज फेंके और अंततः संसद परिसर में मार्च भी निकाला। अध्यक्ष ओम बिरला को हालात देखते हुए सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित करनी पड़ी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए स्पष्ट कहा कि यह विधेयक गरीबों मजदूरों और ग्रामीण भारत के भविष्य को ध्यान में रखकर लाया गया है। उन्होंने मनरेगा के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रारंभ में यह नरेगा था महात्मा गांधी का नाम बाद में जोड़ा गया। वर्ष 2009 के चुनाव से पहले कांग्रेस को गांधी याद आए और वोट की राजनीति के चलते नाम बदला गया। शिवराज सिंह के इस बयान ने सदन में तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी और विपक्ष ने इसे महात्मा गांधी के अपमान से जोड़ने की कोशिश की। सरकार का तर्क है कि वीबीजी राम जी विधेयक का मूल उद्देश्य रोजगार की गारंटी को मजबूत करना और आजीविका के नए अवसर पैदा करना है। इस विधेयक के तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। अब तक इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाती थी लेकिन नए प्रावधानों के अनुसार राज्यों को भी 10 से 40 प्रतिशत तक योगदान देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे राज्यों की भागीदारी बढ़ेगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में जवाबदेही आएगी। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र सरकार गरीबों पर बोझ डाल रही है और राज्यों पर वित्तीय दबाव बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा ताकि इसके हर पहलू पर विस्तार से विचार हो सके। विपक्ष का कहना है कि रोजगार गारंटी जैसी संवेदनशील योजना में जल्दबाजी ठीक नहीं है और सरकार को व्यापक सहमति बनानी चाहिए थी।

शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि नाम को लेकर विरोध करना उचित नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि देश में 55 योजनाओं के नाम राजीव गांधी के नाम पर हैं 74 सड़कों के नाम राजीव गांधी के नाम हैं और 15 नेशनल पार्क जवाहरलाल नेहरू के नाम पर हैं। उन्होंने कहा कि नाम रखने की सनक कांग्रेस की पुरानी आदत रही है और आज जब सरकार विकास की नई सोच के साथ आगे बढ़ रही है तो एक नाम को लेकर हंगामा किया जा रहा है।

भाजपा का कहना है कि महात्मा गांधी उनके लिए भी उतने ही प्रेरणास्रोत हैं जितने किसी और के लिए। शिवराज सिंह ने कहा कि हम भेदभाव नहीं करते बापू हमारी प्रेरणा हैं और हमारे विश्वास हैं। कांग्रेस यह दावा कर रही है कि वही गांधी की सच्ची अनुयायी है लेकिन व्यवहार में उसने हमेशा गांधी के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार गरीबों की योजनाओं से गांधी का नाम हटाकर अपनी विचारधारा थोपना चाहती है। उनका कहना था कि मनरेगा ने करोड़ों गरीबों को सहारा दिया और आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कांग्रेस का दावा है कि गरीबों का दर्द वही समझती है क्योंकि उसने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। सरकार ने इस पर तीखा जवाब देते हुए कहा कि गरीबी हटाओ का नारा केवल नारा बनकर रह गया। शिवराज सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी के दौर में नारे दिए गए लेकिन गरीब जनता पर बोझ बढ़ता गया। गरीबी वास्तव में कम नहीं हुई बल्कि योजनाओं का लाभ सीमित वर्ग तक सिमट कर रह गया। उन्होंने कहा कि आज देश विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है और जो लोग आजादी के बाद दशकों तक गरीबी का घूंट पीते रहे उनकी तौहीन यह कहकर की जा रही है कि विकास की नई सोच गलत है। सरकार का यह भी आरोप है कि कांग्रेस अब अल्पसंख्यकों की हितैषी बनने का दावा कर रही है लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति ने देश के बहुसंख्यक समाज को नुकसान ही पहुंचाया है। तुष्टिकरण किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं होता और इससे देश की एकता और विकास दोनों प्रभावित होते हैं।वीबीजी राम जी विधेयक के समर्थकों का कहना है कि यह कानून केवल रोजगार की गारंटी नहीं देता बल्कि आजीविका के नए साधन भी खोलता है। इसमें कौशल विकास स्थानीय संसाधनों के उपयोग और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे गांवों से शहरों की ओर पलायन रुकेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

विरोधियों का तर्क है कि नाम बदलने से ज्यादा जरूरी है कि जमीनी स्तर पर योजना का क्रियान्वयन सही हो। उनका कहना है कि पहले से मौजूद मनरेगा में मजदूरी भुगतान में देरी भ्रष्टाचार और काम की कमी जैसी समस्याएं हैं। यदि इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो नया नाम और नया ढांचा भी अपेक्षित परिणाम नहीं देगा।

संसद के भीतर और बाहर जो दृश्य देखने को मिले उन्होंने यह साफ कर दिया कि यह बहस केवल रोजगार नीति तक सीमित नहीं है। यह विचारधाराओं की टकराहट है। एक ओर सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखकर पुरानी योजनाओं को नए ढांचे में ढालना चाहती है। दूसरी ओर विपक्ष इसे ऐतिहासिक विरासत और गरीबों के अधिकारों से जोड़कर देख रहा है। ओम बिरला द्वारा सदन की कार्यवाही स्थगित किया जाना इस बात का संकेत है कि संवाद की जगह टकराव बढ़ रहा है। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है लेकिन जब नारेबाजी और हंगामा चर्चा पर हावी हो जाए तो नीति निर्माण प्रभावित होता है। अंततः सवाल यही है कि वीबीजी राम जी विधेयक गरीबों और मजदूरों की जिंदगी में कितना बदलाव लाएगा। नाम चाहे जो हो जनता को रोजगार समय पर मजदूरी और सम्मानजनक जीवन चाहिए। यदि यह कानून उन अपेक्षाओं पर खरा उतरता है तो राजनीतिक शोर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। लेकिन यदि जमीनी हकीकत में सुधार नहीं हुआ तो यह बहस और तेज होगी। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां विकास और विरासत दोनों का संतुलन जरूरी है। रोजगार की गारंटी केवल कागजों पर नहीं बल्कि खेत खलिहानों और गांव की गलियों में दिखनी चाहिए। यही इस विधेयक की असली कसौटी होगी और यही तय करेगा कि वीबीजी राम जी इतिहास में एक सार्थक कदम माना जाएगा या केवल नाम की राजनीति का एक और अध्याय।

(वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, स्तम्भकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

ईमानदारी सर्वोत्तम

एक राजा ने अपने उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए राज्य के सभी नौजवानों को एक-एक बीज दिया और कहा, इसे गमले में लगाकर सींचना और एक वर्ष के पश्चात मेरे पास लेकर आना। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा, उसे राजा घोषित किया जाएगा। सब बीज लेकर खुशी-खुशी लौटे। पांच-छह दिन गुजर जाने पर भी जब बीज अंकुरित नहीं हुआ, तो सबने उसी प्रकार का बीज नर्सरी से खरीदकर अपने-अपने गमले में लगा दिया और सींचने लगे। इन सबमें केवल भोलू नाम का नौजवान ही ऐसा था, जिसने दूसरा बीज खरीदने का दुस्साहस नहीं किया। कुछ दिनों के पश्चात सभी युवा अपने-अपने हरे-भरे गमले के साथ राजा के सम्मुख पेश हुए, केवल भोलू ही खाली गमले के साथ कोने में नजरें चुराए खड़ा था। राजा ने उसे पास बुलाया और घोषणा कर दी कि भोलू ही मेरा उत्तराधिकारी है।

जब जनता ने उसके खाली गमले को प्रश्नवाचक नजरों से देखा, तो राजा ने सभी के समक्ष यह भेद खोला कि मैंने उबले हुए बीज सभी को दिए थे। भोलू ने उसी उबले बीज को सींचा, जबकि शेष सभी ने राजा बनने के लिए बीज बदल लिए। ये बड़े-बड़े पौधे बेईमानी की कहानी कह रहे हैं। सत्य तो यही है कि बीज तो अंकुरित होना ही नहीं था, बावजूद इसके भोलू

हिम्मत व ईमानदारी से अपना खाली गमला ही मेरे पास लेकर आया। इसलिए अगला राजा भोलू ही होगा। यदि हम बुद्धि रूपी जमीन पर ईमानदारी का बीजारोपण कर उसे सींचेंगे, तो निसंदेह उस पर विश्वास रूपी मीठे फल निकलेंगे।

विचार मंथन

दुनिया भर के राजनेताओं और पूंजीपतियों के काले कारनामे

(लेखक-सनत जैन)

अमेरिका में 'एप्सटीन फाइलों' में दर्ज अय्याशी के फोटो को लेकर वैश्विक राजनीति, कॉरपोरेट जगत और मीडिया में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। कहा जा रहा है, इन फाइलों में दुनिया के प्रभावशाली नेताओं, उद्योगपतियों और चर्चित हस्तियों के नाम उनके फोटो और वीडियो जिसमें नाबालिग बच्चियों के साथ यौन कृत्य की गाथा दर्ज हैं। इसकी कुछ तस्वीरें व दस्तावेज़ सार्वजनिक होने की चर्चा अमेरिका में है। यह मुद्दा जितना सनसनीखेज़ है, उतना ही संवेदनशील और गंभीर माना जा रहा है। इसमें नाबालिगों के शोषण जैसे जघन्य अपराध के आरोपों के सबूत होने की बात कही जा रही है। सबसे अहम सवाल यह है, इसका सच क्या है, या अफवाह है। किसी भी व्यक्ति का नाम किसी फाइल, कैलेंडर या कथित सूची में होना, अपने-आप में अपराध सिद्ध नहीं करता है। लोकतांत्रिक समाज में कानून का मूल सिद्धांत है, जब तक दोष सिद्ध न हो, तब तक कोई दोषी नहीं माना जाता है। तस्वीरें, संदर्भ और कथन की प्रामाणिकता, संदर्भ और जांच आवश्यक है। बिना सत्यापन के आरोप केवल व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं। न्याय की प्रक्रिया को भी कमजोर करते हैं। इसके बावजूद ऐप्सटीन फाइलों की यह बहस सत्ता और पूंजी के गठजोड़ के साथ-साथ अनैतिकता एवं मानव ट्रैफिकिंग को लेकर जवाबदेही कैसे सुनिश्चित हो। प्रभावशाली लोग अपने आप को कानून से ऊपर समझें, तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। इसमें ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस एंड्रयू, बिल किलिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेटस, एलन डर्सोविटज, घिसलेन मेक्सवेल, माइकल जेक्सन, डेविड, कोयर फील्ड, लियोनार्डो नाओमी केंपवेल, ल्वेस वेक्सनर तथा भारत के बड़े उद्योगपतियों एवं दो नेताओं के नाम चर्चित हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग तेज होती जा रही है कि एप्सटीन के अपराधों की फाइलों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो। पीड़ितों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दोष सिद्ध होने पर सख़्त सज़ा दी जाए। चाहे आरोपी कितना भी ताकतवर क्यों न हो। अमेरिका की अदालत और अमेरिका के स्वतंत्र मीडिया की भूमिका यहां पर निर्णायक है। सनसनी फैलाने के बजाय तथ्यों की जांच, स्रोतों की पुष्टि की जांच जरूरी है। संपादकीय विवेक यही कहता है, आरोपों को अदालती जांच के दायरे में रखा जाए। जो आरोप दुनिया भर के राजनेताओं और बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर लगाए जा रहे हैं। यह मामला अमेरिका की अदालत में है। अदालत में जिनके नाम आरोप हैं उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका मिले। अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसमें अमेरिका के बड़े-बड़े राजनेताओं और पूंजीपतियों के नाम है। इस पूरे कांड के मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी है। जांच एजेंसियों और अदालत के पास जो सबूत हैं, अब अदालत के विवेक पर होगा, कि वह किस तरह से इस मामले की जांच को आगे बढ़ाए। अदालती सबूत के आधार पर यह मामला बड़ा संवेदनशील हो गया है। इसका असर कई देशों के राजनेताओं और बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर पडना तय है। अदालत की इस कार्रवाई से सत्ता और पूंजीपतियों के गठजोड़ को किस तरह से अनैतिक तौर पर एक दूसरे को प्रभावित किया जाता है, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम भी चर्चाओं में है। एलन मस्क ने इस मामले की जांच कराने की बात कही थी, लेकिन अब वह इस मामले में कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह से फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं, उसने अमेरिका की राजनीति में भारी हलचल मचा दी है। भारत की राजनीति में भी इस फाइल को लेकर हलचल बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया के दौर में जानकारी आग की तरह फैलती है। सोशल मीडिया में कुछ जानकारी सही होती है, कुछ गलत भी होती है। सोशल मीडिया को लेकर प्रामाणिक रूप से कोई बात कहना संभव नहीं हो पाता है। सोशल मीडिया में जो प्रसारित होता है, उसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया तुरंत होती है। यह मामला केवल कुछ नामों या तस्वीरों तक सीमित नहीं है। बल्कि सत्ता और पूंजीपतियों के गठजोड़, कानून व्यवस्था सामाजिक और धार्मिक नैतिकता से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं पर भी महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चों का यौन शोषण हुआ है, ऐसी स्थिति में उन्हें न्याय मिलना ही चाहिए। अगर आरोप निराधार हैं, तो सच सामने आना चाहिए। लोकतंत्र मे शासन व्यवस्था की सच्चाई, निष्पक्षता और प्रमाणों के साथ सामने आए। जांच, कानून व्यवस्था और अदालतों पर भरोसा रखना ही समझदारी भरा एकमात्र रास्ता है। एप्स्टीन फाइलों को लेकर अमेरिका, भारत, इजराइल एवं अन्य कई देशों में जिस तरह से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं, उसे देखते हुए कहा जा रहा है, कई देशों के बड़े-बड़े राजनेताओं और पूंजीपतियों को एप्स्टीन फाईलों मे दर्ज अपराध उजागर होने के बाद बड़ा खामियाजा आरोपियों को भुगतना पड़ सकता है। इसको लेकर दुनिया के कई महत्वपूर्ण देशों में राजनीतिक अस्थिरता बढी है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

श्रीराम फाइनेंस में 4 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेगा जापान का एमयूएफजी समूह

नई दिल्ली। जापान की मित्सुबिशी यूएफजे वित्तीय समूह (एमयूएफजी) के श्रीराम फाइनेंस में चार अरब डॉलर से अधिक के निवेश की उम्मीद है। श्रीराम फाइनेंस भारत के निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। सूत्रों ने बताया कि एमयूएफजी श्रीराम फाइनेंस में 20 प्रतिशत का हिस्सेदारी खरीदेगा और यहां भारतीय वित्तीय सेवा क्षेत्र के सबसे बड़े निवेशों में से एक हो सकता है। इस लेन देन के होने के बाद भी श्रीराम समूह एनबीएफसी का सबसे बड़ा शेयरधारक व प्रवर्तक रहेगा। सूत्रों के मुताबिक श्रीराम फाइनेंस की कॉरपोरेट पहचान बनी रहेगी। श्रीराम समूह की श्रीराम फाइनेंस में 24.98 प्रतिशत हिस्सेदारी है। श्रीराम समूह ने श्रीराम कैपिटल और श्रीराम वैल्यू सर्विसेज के जरिए श्रीराम फाइनेंस में निवेश किया है। इसमें दक्षिण अफ्रीका की सैनलाम लाइफ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी 0.41 प्रतिशत है। इससे प्रवर्तक की कुल हिस्सेदारी 25.39 प्रतिशत हुई है। श्रीराम फाइनैंस को इस लेन देन के लिए ओपन ऑफर की आवश्यकता नहीं होगी। इसका कारण यह है कि हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरी तरह से शेयरों के प्राथमिक निर्गमन के माध्यम से किया जाएगा। श्रीराम फाइनैंस ने इस सप्ताह की शुरुआत में स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया कि उसका बोर्ड बैठक करेगा। इसमें राइट्स इश्यू, तरजीही आवंटन, योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट या किसी अन्य तरीके से धन जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

प्लेटिनम 18 साल के रिकॉर्ड स्तर पर

मुंबई। सोने-चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के साथ प्लेटिनम भी निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दे रहा है। ग्लोबल मार्केट में प्लेटिनम के दाम 18 साल के ऊंचे स्तर 1,975 डॉलर प्रति औंस (1,78,227 रुपए प्रति 28.35 ग्राम) पर पहुंच गए। निवेशक कमजोर होती करेंसी से संभावित नुकसान से बचाव (हेजिंग) के लिए प्लेटिनम में निवेश कर रहे हैं। सोना-चांदी जरूरत से ज्यादा महंगे होने से ये थोड़े सस्ते विकल्प नजर आ रहे हैं। 2025 में अब तक इसकी कीमत 121 प्रतिशत बढ़ चुकी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक भारत में प्लेटिनम की औसत कीमत 61,513 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। 2024 के आखिर में यह 27,560 रुपए और 2020 के आखिर में 24,910 रुपए थी।

इस महीने में 211 लाख टन कच्चे तेल का आयात, बिल यथावत रहा

-2026 में भी कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रहने की संभावना

नई दिल्ली। नवंबर महीने में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कच्चे तेल आयात की मात्रा में 11 फीसदी बढ़ोतरी हुई, जबकि आयात बिल यथावत रहा। पेट्रोलियम प्लानिंग ऐंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर में देश का तेल आयात बिल 9.9 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले की तुलना में अपरिवर्तित है। भारत ने इस महीने के दौरान 211 लाख टन कच्चे तेल का आयात किया, जो पिछले साल की समान अवधि में आयात किए गए 189 लाख टन की तुलना में काफी ज्यादा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा आपूर्ति के डर के कारण 2025 में कच्चे तेल की कीमत कम रही है। इसकी वजह से ज्यादा तेल खरीद के बावजूद भारत का आयात बिल कम रहा। भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत नवंबर 2025 में औसतन 64.31 डॉलर प्रति बैरल रही, जबकि पिछले साल यह 73.02 डॉलर प्रति बैरल थी। अप्रैल से नवंबर की अवधि में देश के कच्चे तेल का आयात बिल करीब 12 फीसदी घटकर 80.9 अरब डॉलर रह गया। आपूर्ति की अधिकता के डर और यूक्रेन व रूस के बीच शांति समझौते की उम्मीदों के बीच बेंचमार्क ब्रेंट इस सप्ताह की शुरुआत में गिरकर 60 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम है।

एयरटेल ने किया शीर्ष पदों पर बदलाव का ऐलान

गोपाल विट्टल बने एक्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन; जनवरी 2026 से शाश्वत शर्मा संभालेंगे एमडी और सीईओ की कमान

नई दिल्ली।

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारती एयरटेल ने एक ऐतिहासिक उत्तराधिकार योजना के तहत अपने शीर्ष नेतृत्व में बड़े फेरबदल की घोषणा की है। पिछले तेरह वर्षों से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ गोपाल विट्टल अब 1 जनवरी 2026 से एक्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन की नई रणनीतिक भूमिका में नज़र आएंगे। उनके स्थान पर वर्तमान सीईओ डेज़ग्निेट शाश्वत शर्मा को कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बदलाव एयरटेल की उस दूरदर्शी सोच का हिस्सा है, जिसके तहत नेतृत्व का हस्तांतरण बेहद सुव्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित किया गया है।

गोपाल विट्टल अपनी नई और व्यापक जिम्मेदारी में भारती एयरटेल सहित उसकी सभी सहायक कंपनियों की कमान संभालेंगे। उन पर समूह स्तर पर डिजिटल रूपांतरण, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क रणनीति और टैलेंट मैनेजमेंट जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों को नई दिशा देने का अहम भार होगा। वहीं, शाश्वत शर्मा जो पिछले एक वर्ष से विट्टल के साथ मिलकर व्यवसाय के हर पहलू पर काम कर रहे थे, अब भारतीय परिचालन का नेतृत्व करेंगे और सीधे विट्टल को रिपोर्ट करेंगे। इस नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही कंपनी ने अपने वित्तीय प्रबंधन को भी नई मजबूती दी है। वर्तमान सीएफओ सौमेन रे को अब ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के उच्च पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि एयरटेल के साथ 12 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अखिल गर्ग अब भारती एयरटेल इंडिया के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का दायित्व संभालेंगे। प्रशासनिक स्तर पर रोहित पुरी को कंपनी सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जबकि पंकज तिवारी ग्रुप कंपनी सेक्रेटरी के रूप में समूह स्तर पर अपनी सेवाएं जारी रखेंगे।

चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने नेतृत्व के इस हस्तांतरण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे निरंतरता और नई ऊर्जा का अनूठा संगम बताया है। उन्होंने कहा कि गोपाल विट्टल के अनुभव और शाश्वत शर्मा की सक्रियता की यह जुगलबंदी एयरटेल को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेलीकॉम कंपनी बनाने के संकल्प को और अधिक सशक्त करेगी।

रुपया तेजी के साथ बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को 62 पैसे की तेजी के साथ ही 89.65 पर बंद हुआ। इससे पहले गत दिवस रुपया 10 पैसे की तेजी के साथ ही 90.27 पर बंद हुआ था। वहीं अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गत दिवस रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.35 पर खुला। कारोबार के दौरान इसमें हल्की मजबूती देखी गई और यह 90.32 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि शुरुआती सत्र में रुपये में कमजोरी भी दर्ज की गई और यह 90.38 के स्तर तक फिसल गया। बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 फीसदी की बढ़त के साथ 98.41 पर रहा, जिससे उभरती मुद्राओं पर दबाव बना रहा।

बिजली मंत्रालय आयात होने वाले सामानों की सूची तैयार कर रहा.....लोकल उत्पादन पर जोर

नई दिल्ली।

बिजली मंत्रालय वर्तमान में आयात होने वाले बिजली क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की सूची तैयार करने के लिए उद्योग के साथ काम में जुटा है। इसका मकसद इन वस्तुओं के लोकल उत्पादन के लिए मदद देना है। सूची में सब सी केबल्स, परमानेंट मैग्नेट्स और उच्च चालकता वाली तांबे की छड़ें शामिल हैं। बिजली मंत्रालय की शाखा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने उद्योग निकाय इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) को भेज पत्र में कहा, 'मौजूदा परिदृश्य में यह पहल जरूरी है, क्योंकि बिजली क्षेत्र उन्नत उपकरणों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। आयात पर निर्भरता के कारण इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जोखिम जुड़े हैं और इनकी कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता है।' इन वस्तुओं के लोकल उत्पादन से केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बल मिलेगा और इनके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ग्रिड का लचीलापन और ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सीईए ने कहा, मंत्रालय के लिए आर्थिक रूप से ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक यथार्थवादी, उद्योग-समर्थित मूल्यांकन आवश्यक है। प्राधिकरण ने आईईईएमए और एबीबी, आदित्य बिड़ला, ह्योसंग, पॉलिकैब, डोंग-वू क्रांटम इंडिया, स्टरलाइट, श्नाइडर, तोशिबा, केईसी और जिंदल एल्युमीनियम सहित उद्योग जगत के प्रमुख हितधारकों के साथ हाल ही में परामर्श के माध्यम से 73 महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की एक सूची बनाई है।

शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद

सेंसेक्स 447, निफ्टी 150 अंक ऊपर आया

मुंबई ।

शेयर बाजार शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये तेजी दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही ऑटो और रियल्टी शेयरों में खरीददारी हावी रहने से आई है। दिन भर के बारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 447.55 अंक बढ़कर 84,929.36 और 50 शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 150.85 अंक उछलकर 25,966.40 पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.67 फीसदी और निफ्टी ऑटो इंडेक्स 1.23 फीसदी ऊपर आया। इसके अलावा, आईटी, पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, एफएमसीजी, मीडिया, एनर्जी, प्राइवेट बैंक , इन्फ्रा और कमोडिटीज के शेयर लाभ में रहे। सेंसेक्स के शेयरों में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, एलएंडटी, ट्रेंट, एचयूएल, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, के शेयर लाभ के साथ ही ऊपर आये। वहीं एचसीएल टेक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों को नुकसान हुआ। आज कारोबार के दौरान लार्जकैप के साथ ही मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में खरीदारी हावी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 718 अंक बढ़कर 60,310.15 और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 230.15 अंक उछलकर 17,390.35 पर बंद हुआ था।

इससे पहले आज सुबह बाजार बढ़त के साथ खुला। सुबह सेंसेक्स बाजार खुलने के बाद 337.06 अंक तेजी के साथ 84,818.87 अंक पर कारोबार

करता दिखा। वहीं निफ्टी भी 95.45 अंक की बढ़त के साथ ही 25,911.00 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। आज एशिया-पैसिफिक बाजारों में खरीदारी देखने को मिली। निवेशक जापान के केंद्रीय बैंक के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अनुमान है कि बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है और दरें 0.75 फीसदी तक पहुंच सकती हैं। इस बीच जापान का निक्केई, ऑस्ट्रेलिया का एएसएक्स 200 और दक्षिण कोरिया के कोस्पी में बढ़त रही। वहीं अमेरिकी बातार वॉल स्ट्रीट में बढ़त रही। एसएंडपी 500 ने चार कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद बढ़त दर्ज की। महंगाई के अनुमान से कम रहने वाले आंकड़ों से 2026 में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ी है।

2030 तक 50 लाख भारतीय छात्रों और युवाओं को एआई से प्रशिक्षित करेगी आईबीएम

मुंबई ।

आईबीएम ने भारत में कौशल विकास के लिए एक बड़े अभियान का ऐलान किया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी 2030 तक 50 लाख भारतीय छात्रों और युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षित करेगा। यह पहल आईबीएम स्किल्सबिल्ड के माध्यम से होगी, जिसका उद्देश्य देश में भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना है और छात्रों और वयस्कों को डिजिटल और नौकरी केंद्रित कौशल तक आसान पहुंच देना है। आईबीएम ने कहा कि कार्यक्रम के जरिए उन्नत तकनीक की शिक्षा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाया जाएगा, इसके तहत स्कूल, विश्वविद्यालय और कारोबारी प्रशिक्षण संस्थानों में एआई और उभरती तकनीकी शिक्षा का विस्तार होगा।

आईबीएम, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर एआई-केंद्रित पाठ्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण, हैकथॉन और इंटर्नशिप जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देगा, जिसका मकसद छात्रों और शिक्षकों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ अरविंद कृष्णा ने कहा कि भारत में एआई और क्वांटम तकनीक में वैश्विक नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि योजना से युवाओं को नई चीजें सीखने, नवाचार और देश के विकास में मदद करने का मौका मिलेगा।

आईबीएम स्कूलों में एआई शिक्षा को मजबूत कर रहा है। वरिष्ठ माध्यमिक छात्रों के लिए

एआई पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है और शिक्षकों को एआई प्रोजेक्ट कुकबुक, शिक्षक मार्गदर्शिका और समझाने वाले मॉड्यूल जैसी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को कंप्यूटेशनल सोच और जिम्मेदार एआई की समझ देना है।

सेबी ने जीरो-कूपन बॉन्ड को 10,000 से कम डिनॉमिनेशन में जारी करने की दी अनुमति

नई दिल्ली।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शर्तों में बदलाव करके जीरो-कूपन बॉन्ड को 10,000 रुपए के कम डिनॉमिनेशन में जारी करने की अनुमति दी है। इसके तहत जारीकर्ता निजी नियोजन के जरिये जारी अपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों और अपरिवर्तनीय तरजीही शेयरों की फेस वैल्यू कम कर सकते हैं। पहले के एक सर्कुलर में सेबी ने जारी करने वालों को ऐसी प्रतिभूतियों की फेस वैल्यू घटाकर 10,000 रुपए करने की इजाजत दी थी, बशर्ते वे फिक्स्ड मैच्योरिटी वाले ब्याज या लाभांश देने वाले साधन हों और उन पर कोई स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन न हो। हालांकि, इस शर्त ने जीरो-कूपन बॉन्ड को बाहर कर दिया, जो समय-समय पर ब्याज नहीं देते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाजार कारोबारियों की प्रतिक्रिया पर जवाब देते हुए सेबी ने माना कि जीरो-कूपन बॉन्ड समय-समय पर मिलने वाले कूपन के बजाय कीमत में बढ़ोतरी पर रिटर्न देते हैं। नियामक ने कहा कि ये बॉन्ड समय के साथ चक्रवृद्धि रिटर्न देते हैं और पोर्टफोलियो में विविधता लाने वाले निवेशक इनका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं।

भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 8 प्रतिशत बढ़कर 17.04 लाख करोड़ हो गया

नई दिल्ली ।

भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अब तक (17 दिसंबर) 8 प्रतिशत बढ़कर 17.04 लाख करोड़ हो गया है। इसकी जानकारी केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को दी गई। आयकर विभाग की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार का कुल सकल कर संग्रह इस साल एक अप्रैल से लेकर 17 दिसंबर तक 20.01 लाख करोड़ रुपए रहा है। इसमें सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 2.97 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया है। इसमें सालाना आधार पर 13.52 प्रतिशत की गिरावट आई है।

शुद्ध प्रत्यक्ष कर में कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 8.17 लाख करोड़ रुपए रही है, जो कि बीते वित्त वर्ष की समान अवधि में 7.39 लाख करोड़ रुपए था। इसमें नॉन-कॉरपोरेट टैक्स की हिस्सेदारी 8.46 लाख करोड़ रुपए थी, जो कि एक साल पहले समान अवधि में 7.96 लाख करोड़ रुपए थी। नॉन-कॉरपोरेट टैक्स में व्यक्तिगत कर और हिंदू अविभाजित परिवारों से वसूलने वाले कर को शामिल किया है। समीक्षा अवधि में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) संग्रह 40,194.77 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 40,114.02 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष में सरकार ने 25.20 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य रखा है, जो कि सालाना आधार पर 12.7 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ वित्त वर्ष 26 में सरकार को 78,000 करोड़ रुपए का एसटीटी

संग्रह होने का अनुमान है। कर संग्रह में इसतरह का इजाफा देखने को मिला है, जब आम बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर प्रणाली के तहत कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया था। इससे बड़ी संख्या आयकर दाताओं का राहत मिली है।

बिजली मंत्रालय आयात होने वाले सामानों की सूची तैयार कर रहा.....लोकल उत्पादन पर जोर

नई दिल्ली।

बिजली मंत्रालय वर्तमान में आयात होने वाले बिजली क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की सूची तैयार करने के लिए उद्योग के साथ काम में जुटा है। इसका मकसद इन वस्तुओं के लोकल उत्पादन के लिए मदद देना है। सूची में सब सी केबल्स, परमानेंट मैग्नेट्स और उच्च चालकता वाली तांबे की छड़ें शामिल हैं। बिजली मंत्रालय की शाखा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने उद्योग निकाय इंडियन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) को भेज पत्र में कहा, 'मौजूदा परिदृश्य में यह पहल जरूरी है, क्योंकि बिजली क्षेत्र उन्नत उपकरणों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। आयात पर निर्भरता के कारण इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला संबंधी जोखिम जुड़े हैं और इनकी कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता है।'

इन वस्तुओं के लोकल उत्पादन से केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बल मिलेगा और इनके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और ग्रिड का लचीलापन और ऊर्जा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सीईए ने कहा, मंत्रालय के लिए आर्थिक रूप से ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक यथार्थवादी, उद्योग-समर्थित मूल्यांकन आवश्यक है। प्राधिकरण ने आईईईएमए और एबीबी, आदित्य बिड़ला, ह्योसंग, पॉलिकैब, डोंग-वू क्रांटम इंडिया, स्टरलाइट, श्नाइडर, तोशिबा, केईसी और जिंदल एल्युमीनियम सहित उद्योग जगत के प्रमुख हितधारकों के साथ हाल ही में परामर्श के माध्यम से 73 महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की एक सूची बनाई है।

चीनी उद्योग की चिंताओं को दूर करने अगले माह कुछ कदम उठाएगी केंद्र सरकार

केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने दिया भरोसा

नई दिल्ली।

केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि केंद्र चीनी उद्योग की चिंताओं को दूर करने के लिए अगले माह कुछ फैसले करेगी। दरअसल, मांग से अधिक उत्पादन होने के कारण गन्ने का बकाया बढ़ने लगा है। यह फैसला चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की लंबे समय से लंबित मांग से जुड़ा है। चीनी कारोबार चीनी का एमएसपी मौजूदा 22 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर करीब 41 रुपये प्रति किलोग्राम करने की मांग कर रहा है। इस क्रम में उद्योग गन्ने से एथनॉल बनाने के मौजूदा 28 प्रतिशत को बढ़ाकर आदर्श रूप से 50 प्रतिशत करने और चीनी का निर्यात मौजूदा 15 लाख टन से बढ़ाने की मांग भी कर रहा है। चीनी सत्र अक्टूबर से सितंबर तक होता है।

केंद्रीय खाद्य सचिव चोपड़ा ने इंडियन शुगर एंड बॉयो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (इस्मा) की वार्षिक बैठक में कहा, 'देखिए, वर्तमान में गन्ना बकाया ज्यादा बड़ा नहीं है।

हमें बताया गया है कि अगले महीने तक बकाया बढ़ना शुरू होगा। फिर खपत से अधिक चीनी का उत्पादन (2025-26 सत्र में) किसानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। यह हम नहीं चाहते

हैं। इसलिए अधिशेष को कम करने के लिए हम जो कुछ औश्र कर सकते हैं, और यकीनन करने वाले है। चोपड़ा ने कहा कि वर्तमान में उठाए कदमों के साथ इस्मा ने अनुमान लगाया है कि 2025-26 सत्र के अंत तक चीनी का समापन स्टॉक करीब 60 लाख टन होगा और सरकार इस कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी ताकि किसानों को बढ़ते बकाया के कारण नुकसान न हो।

उधर इस्मा के निवर्तमान अध्यक्ष गौतम गोयल ने कहा कि उनके प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 30 नवंबर तक महाराष्ट्र में गन्ना बकाया पहले ही करीब 2,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है जबकि उत्तर प्रदेश के आंकड़े अभी भी प्रतीक्षित हैं। दरअसल, मॉनसून की अवधि बढ़ने के कारण उत्तर प्रदेश में पेराई देर से शुरू हुई।

देश के कुल चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत से अधिक है।

एनसीएलटी के 50 और अपीली न्यायाधिकरण के 2 नए न्यायालय खोलने का रास्ता साफ

-केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी

नई दिल्ली। कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के 50 और अपीली न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के 2 नए न्यायालय खोलने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने बताया कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर प्रवर समिति के साथ साझा की है। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने समिति को बताया है कि वह 'आईबीसी प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण नियम' के तहत नियम बनाएगा, ताकि समयसीमा का पालन होना सुनिश्चित हो सके। मंत्रालय ने समिति को बताया कि 'यह फैसला करने वाले प्राधिकरणों की इंफ्रा, कार्यात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यानपूर्वक करने के लिए किया जाएगा।

प्रवर समिति ने कहा, न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करने के लिए संबंधित प्रावधानों को सहायक कानूनों के साथ मजबूत करने की जरुरत हैं। विभिन्न हितधारकों ने समिति को बताया कि न्यायिक क्षमता का विस्तार करने या पीठों की संख्या बढ़ाने और इंफ्रा के सुधार के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाकर न्यायनिर्णय प्रक्रिया के पुनर्गठन की जरूरत है। एनसीएलटी में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल स्वीकृत संख्या 63 है। एनसीएलटी के पीठों में 31 मार्च, 2025 तक केवल 3 पद रिक्त थे। मौजूदा आईबीसी ढांचे के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान शुरू करने वाले आवेदन को 14 दिनों के भीतर स्वीकार होना चाहिए, जबकि हकीकत में दिवाला आवेदन स्वीकार करने में न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों को औसतन एक साल से अधिक लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सदस्यों की कमी और अपेक्षित संख्या न होने के कारण न्यायाधिकरण सप्ताह में केवल कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ही बैठते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यहां तक कि उन न्यायाधिकरणों में, जहां कोई रिक्ति नहीं है, अपेक्षित इन्फ्रा के अभाव के कारण पीठों को रोटेशन के आधार पर कोर्टरूम या हॉल साझा करने के लिए मजबूर होने पड़ता है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

ट्रैविस हेड ने ब्रैडमैन और स्मिथ के बाद बनाया खास रिकॉर्ड, इंग्लैंड को एडिलेड में खूब 'पीटा'

एडिलेड (ऑस्ट्रेलिया) (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलियाई स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने शुक्रवार को अपने घरेलू स्टेडियम एडिलेड ओवल में इंग्लैंड को खूब 'पीटा' (शतक) और डॉन ब्रैडमैन तथा स्टीव स्मिथ के साथ खास रिकॉर्ड बना दिया है। हेड शानदार शतक लगाने के बाद अपने देश के एक क्रिकेट मैदान पर लगातार 4 शतक लगाने वाले क्रिकेट दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।

ट्रैविस ने मौजूदा एशेज सीरीज के दौरान अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। कप्तान बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर और ब्रायडन कार्स की शतकीय साझेदारी के बाद संघर्ष कर रही इंग्लैंड टीम के लिए उम्मीद और वादे से भरी सुबह की शुरुआत हुई जिसमें जेक वेदरल्ड को आउट करके शुरुआती विकेट लिया गया, लेकिन यह एक और बुरे सपने वाले दिन में बदल गया क्योंकि ट्रैविस ने इंग्लिश लाइन-अप की धुनाई की और दिन का अंत 196 गेंदों में शानदार 142* रन बनाकर किया जिसमें 13 चौके और दो छक्के शामिल थे, स्ट्राइक रेट 72 से अधिक था।

क्लार्क के बाद ऐसा करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई

हेड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क के बाद दूसरे बल्लेबाज हैं जिन्होंने जनवरी 2012 और दिसंबर 2014 के बीच एडिलेड में लगातार चार टेस्ट शतक बनाए हैं। उन्होंने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ (175), 2024 में उसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ (119) और पिछले साल भारत के खिलाफ (140) एडिलेड में शतक बनाए हैं। अब उन्होंने एक और शानदार शतक लगाया है जो उनके घरेलू स्टेडियम एडिलेड ओवल में उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन को जारी रखता है।

दिग्गजों की लिस्ट में शामिल

हेड ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डॉन ब्रैडमैन (1928 से 1932 तक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में), माइकल क्लार्क (2012 से 2014 तक एडिलेड में), स्टीव स्मिथ (2014 से 2017 तक स्ष्ठत्र में) और इंग्लिश दिग्गज वैली हैमंड (1928 से 1936 तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में) की एलीट कंपनी में शामिल हो गए हैं, जो किसी खास ऑस्ट्रेलियाई मैदान पर लगातार चार टेस्ट शतक बनाने वाले पांचवें बल्लेबाज हैं। एडिलेड ओवल में हेड ने आठ मैचों और 11 पारियों में 87.33 की औसत से 786 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं और उनका बेस्ट स्कोर 175 है।

इस साल टेस्ट में ट्रैविस हेड का रिकॉर्ड

इस साल 10 टेस्ट और 19 पारियों में उन्होंने 43.00 की औसत और 79.71 के स्ट्राइक रेट से 731 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक, तीन अर्धशतक और 142* का बेस्ट स्कोर शामिल है। चल रही एशेज सीरीज में हेड तीन मैचों और छह पारियों में 70.20 की औसत और 86.24 के स्ट्राइक रेट से 351 रन बनाकर सबसे आगे हैं, जिसमें दो शतक और 142* का बेस्ट स्कोर शामिल है।

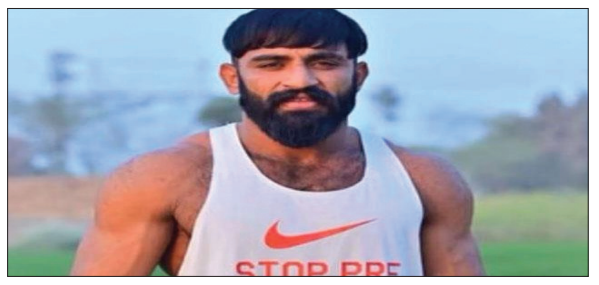

भारत टीम के लिए खेला पाकिस्तान का मशहूर कबड्डी खिलाड़ी, झंडा भी लहराया, तस्वीरें वायरल होने पर बुरा फंसा

कराची (एजेंसी)। पाकिस्तानी के लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्लाह राजपूत पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वह 16 दिसंबर को बहरीन में एक निजी टूर्नामेंट में भारतीय टीम के लिए खेले थे। जीसीसी कप में भारतीय शर्ट पहने और भारतीय झंडा लहराते हुए उबैदुल्लाह के वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद वह बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं।

पाकिस्तान कबड्डी महासंघ (PKF) के सचिव राणा सरवर ने कहा कि पीकेएफ की एक आपात बैठक 27 दिसंबर को बुलाई गई है जिसमें इस मामले पर चर्चा की जाएगी और राजपूत तथा कुछ अन्य खिलाड़ियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

सरवर ने कहा, 'मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह एक निजी टूर्नामेंट था जिसमें आयोजकों द्वारा प्रतियोगिता में भारत, पाकिस्तान, कनाडा, ईरान आदि नामों से निजी टीमें बनाई गई थीं लेकिन सभी टीमों में अपने-अपने देश के खिलाड़ी थे। भारतीय खिलाड़ियों ने भारतीय निजी टीम का प्रतिनिधित्व किया और उबैदुल्लाह उनके लिए खेले जो इन परिस्थितियों में स्वीकार्य नहीं है।'

सरवर ने यह भी दावा किया कि 16 पाकिस्तानी खिलाड़ी महासंघ या पाकिस्तान खेल बोर्ड से बिना किसी इजाजत के बहरीन गए थे। उन्होंने कहा, 'इसलिए इन खिलाड़ियों के खिलाफ भी पाकिस्तान टीम के नाम पर गलत तरीके से खेलने के लिए कार्रवाई की जाएगी।' राजपूत ने माफी मांगी है और साफ किया है कि उन्हें बहरीन में इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्हें एक निजी टीम में शामिल किया गया। उन्होंने कहा, 'लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने टीम का नाम भारतीय टीम रखा था और मैंने आयोजकों से कहा कि वे भारत और पाकिस्तान के नाम इस्तेमाल नहीं करें।'

कुलदीप यादव को लियोनेल मेसी का खास तोहफा, भारतीय स्पिनर हुआ भावुक

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट और विश्व फुटबॉल का अनोखा संगम उस वक्त देखने को मिला, जब टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को फुटबॉल के महान खिलाड़ी लियोनेल मेसी से साइन की हुई अर्जेंटीना जर्सी मिली। यह खास पल मेसी के 'त्न्न्ञ्ञ इंडिया टूर 2025' के दौरान राजधानी दिल्ली में देखने को मिला। इस मुलाकात ने न सिर्फ खेल प्रेमियों का दिल जीता, बल्कि यह दिखाया कि खेल सीमाओं और खेलों से परे एक-दूसरे को जोड़ने की ताकत रखते हैं।

लियोनेल मेसी के भारत दौरे के दौरान कुलदीप यादव को अर्जेंटीना की ऑटोग्राफ वाली जर्सी भेंट की गई। यह तस्वीर एडिडास इंडिया के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साझा की गई, जिसमें कुलदीप के साथ भारत के नामी पैरा एथलीट भी नजर आए। इस खास मौके पर कुलदीप की खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि वह लंबे समय से मेसी और एफसी बार्सिलोना के बड़े प्रशंसक रहे हैं।

इस आयोजन में सिर्फ कुलदीप यादव ही नहीं, बल्कि भारत के कई दिग्गज एथलीटों को मेसी से मिलने का मौका मिला। दो बार के पैरालंपिक भाला फेंक चैंपियन सुमित अंतिल, पैरा हाई-जंप स्टार निशाद कुमार, बॉक्सिंग की स्टार खिलाड़ी निकहत ज़रीन और महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर भी इस यादगार पल का हिस्सा बने।

भारत अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पहुंचा, 11 साल बाद पाकिस्तान से होगा खिताबी मुकाबला

दुबई (एजेंसी)। उप-कप्तान विहान मल्होत्रा की शानदार स्ट्रोक-प्ले को आरोन जॉर्ज के संयम ने बखूबी साथ दिया जिससे भारत अंडर-19 ने शुक्रवार को बारिश से प्रभावित सेमीफाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई।

बारिश के कारण मैच 20-20 ओवर का कर दिया गया जिसके बाद भारतीय गेंदबाजी यूनिट जिसने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है, ने श्रीलंका को 20 ओवर में 8 विकेट पर 138 रन पर रोक दिया। जवाब में बाएं हाथ के बल्लेबाज मल्होत्रा (45 गेंदों में 61 रन नाबाद), जिन्हें हाल ही में हुए IPL मिनी ऑक्शन में RCB ने खरीदा था, ने आसानी से फ्लिक और पुल शॉट खेलते हुए कुछ चौकों के अलावा दो छक्के भी लगाए। उनके साथी और इस टूर्नामेंट में भारत के संकटमोचक जॉर्ज (49 गेंदों में 58 रन नाबाद) ने अपने स्ट्रोक्स में तकनीकी रूप से परफेक्ट थे जिससे भारत ने 18 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। फाइनल में भारत की आठवीं उपस्थिति मल्होत्रा और जॉर्ज के बीच तीसरे विकेट के लिए अटूट 114 रन की साझेदारी पर आधारित थी।

दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया और ये दोनों पड़ोसी देश 11 साल के अंतराल के बाद महाद्वीपीय फाइनल में मिलेंगे। पिछली बार जब भारत -19 ने 2014 में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, तो उस टीम में श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, संजू सैमसन और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी शामिल थे।

भारत अंडर-19 की शुरुआत अच्छी नहीं रही, जब किशोर IPL सनसनी आयुष म्हात्रे (7) और वैभव सूर्यवंशी (9) को तेज गेंदबाज रसिथ निमसार ने आउट कर दिया। म्हात्रे जिनका टूर्नामेंट खराब रहा है, निमसार की एक छोटी गेंद पर गलत टाइमिंग से पुल शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए। निमसार ने सूर्यवंशी के लिए अपनी गति में बदलाव किया जिन्होंने बल्ले का मुंह बंद करने की कोशिश की लेकिन गेंद बल्ले के किनारे पर लगी और हवा में उछल गई।

हालांकि मल्होत्रा ने निमसार की गेंद पर फ्लिक करके छक्का लगाकर शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जॉर्ज के मामले में ऑफ-स्पिनर कविजा गमागे की गेंद पर एक शानदार ड्राइव ने उनकी क्लास दिखाई। श्रीलंका अंडर19 अभी भी दुनिथ सिगेरा द्वारा फेंके गए 13वें ओवर तक मुकाबला कर रही थी, जहां मल्होत्रा ने पहले बाउंड्री के लिए एक छोटा, मजबूत पुल शॉट खेला, उसके बाद एक्स्ट्रा कवर के जरिए एक ड्राइव और फिर एक और फ्रंट-फुट पुल शॉट खेला जो घास के किनारे पर गिरा।

फील्डिंग चुनने के बाद भारतीय टीम की बॉलिंग यूनिट ने पहले 6 ओवरों में श्रीलंका को 28 रन पर 3 विकेट पर रोककर अच्छा प्रदर्शन किया जिसके बाद कप्तान विमथ दिंसारा (32) और चमिका हेनाटिगाला (42) ने अगले छह ओवरों में 45 रन जोड़कर पारी को संभाला। हालांकि यह सेथमिका सेनेविरत्ने की छोटी लेकिन तेज़ पारी थी - 22 गेंदों में 30 रन - जिसने श्रीलंका को 135 रन के पार पहुँचाया। भारत के लिए, स्पिनर कनिष्क चौहान और हेनिल पटेल ने दो-दो विकेट लिए।

फाइनल के चार मिनट में बदला खेल, मोरक्को ने जॉर्डन को हराकर अरब कप का खिताब जीता

दोहा । अब्दररज्जाक हामेद अल्लाह के दो गोल से मोरक्को ने अतिरिक्त समय तक चले अरब कप के फाइनल में जॉर्डन को 3-2 से पछाड़कर खिताब अपने नाम किया। लुसैल स्टेडियम में हामेद अल्लाह ने 88वें मिनट में बराबरी का गोल दागा और फिर 100वें मिनट में विजयी गोल करके मोरक्को को 'अफ्रीका कप ऑफ नेशंस' से पहले अरब कप ट्रॉफी दिला दी। फाइनल के चार मिनट से भी कम समय में ओसामा तन्नाने ने सेंटर लाइन के पीछे से शानदार स्ट्राइक लगाकर मोरक्को को बढ़त दिलाई थी। अली ओलवान के 48वें मिनट में हेडर से गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया और 68वें मिनट में पेनल्टी से जॉर्डन को बढ़त दिला दी।

विश्व कप की तैयारियों के लिए खुद को चुनौती देना जरूरी : वरुण चक्रवर्ती

अहमदाबाद । भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने कहा कि टी20 विश्व कप की तैयारी में उनका पूरा ध्यान अपनी गेंदबाजी की लेंथ पर भरोसा करने, आत्मविश्वास बनाए रखने और आसान दिखने वाले मैचों में भी खुद को मानसिक रूप से चुनौती देने पर केंद्रित है। इस 34 साल के खिलाड़ी ने 32 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 51 विकेट लिए हैं। इसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा पांच मैचों की श्रृंखला के शुरुआती तीन मैचों में लिए गए छह विकेट भी शामिल हैं।

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में सात फरवरी से आठ मार्च तक होने वाले टी20 विश्व कप में भारत के खिताब की रक्षा के लिए चक्रवर्ती काफी अहम खिलाड़ी है। उन्होंने 'जियोस्टार' के 'फॉलो द ब्लूज' कार्यक्रम में कहा, '' विश्व कप की तैयारी के लिए खुद पर लगातार दबाव बनाए रखना बहुत जरूरी है।' कर्नाटक में जन्में इस गेंदबाज ने कहा, ''जब कोई चुनौती न हो तब भी आपको खुद को चुनौती देनी होगी। अगर कोई मैच आसान लगे तो आपको मानसिक रूप से दबाव बनाना होगा और खुद को चुनौती देना शुरू करना होगा।' उन्होंने कहा, 'उनके लिए आत्मविश्वास, सही लेंथ पर गेंदबाजी करना और विपक्षी टीम को समझना बहुत जरूरी है। यह एक अहम बात है जिसे मैं विश्व कप में ध्यान में रखना चाहता हूं। विपक्षी टीम को बेहतर ढंग से समझने से मुझे लगता है कि मैं अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं।' चक्रवर्ती ने कहा कि बुनियादी बातों पर टिके रहना और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी हालिया सफलता की कुंजी रही है। उन्होंने कहा, 'मेरी योजना काफी सरल है, बुनियादी बातों पर ध्यान देना और अपनी लेंथ पर गेंदबाजी करना। कभी-कभी यह कारगर साबित होता है और शुक्र है कि पिछले तीन मैचों में यह कारगर रहा है। मैं अगले मैच में भी यही रणनीति अपनाऊंगा।'

विजय हजारे ट्रॉफी: मुंबई की संभावित टीम से रोहित-जायसवाल बाहर!

नई दिल्ली (एजेंसी)। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 से पहले मुंबई क्रिकेट टीम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के साथ-साथ ज्ञ20द्ध कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे को कथित तौर पर मुंबई की शुरुआती टीम में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, चयन समिति ने इस पर स्थिति साफ करते हुए संकेत दिए हैं कि इन खिलाड़ियों के लिए दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं।

24 दिसंबर से शुरू होगा मुंबई का विजय हजारे अभियान

मुंबई की टीम 24 दिसंबर से विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में अपने सफर की शुरुआत करेगी। टीम को एलीट ग्रुप ष्ट में रखा गया है और ग्रुप स्टेज के सभी मुकाबले जयपुर में खेले जाएंगे। इस बार टीम की कमान अनुभवी ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर को सौंपी गई है, जिनसे संतुलित नेतृत्व और ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद होगी।

बड़े नाम शुरुआती टीम से बाहर

रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई की घोषित टीम में कई बड़े भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के नाम नहीं हैं। इनमें कप्तान रोहित शर्मा, युवा स्टार यशस्वी जायसवाल, भारत के टी20आई कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर शिवम दुबे शामिल हैं। इन खिलाड़ियों का बाहर होना फैंस के लिए चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन इसके पीछे रणनीतिक और फिटनेस से जुड़े कारण माने जा रहे हैं।

बाहर होने का मतलब बाहर रहना नहीं

मुंबई चयन समिति ने साफ कर दिया है कि इन खिलाड़ियों का टीम सूची में नाम न होना यह तय नहीं करता कि वे टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। चयनकर्ताओं के मुताबिक, जो भी भारतीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी उपलब्ध होंगे, उन्हें बाद में टीम में शामिल किया जा सकता है। यानी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

यशस्वी जायसवाल की फिटनेस पर नजर

यशस्वी जायसवाल के मामले में फिटनेस एक अहम कारण है। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार शतक जड़ने के बाद उन्हें एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। हालांकि अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन उनकी मैच फिटनेस का अंतिम आकलन टूर्नामेंट शुरू होने के करीब किया जाएगा।

BCCI का खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने का संदेश

गौरतलब है कि BCCI ने सभी भारतीय खिलाड़ियों से घरेलू क्रिकेट, खासकर विजय हजारे ट्रॉफी में भाग लेने पर जोर दिया है। यह टूर्नामेंट 50 ओवर फॉर्मेट का सबसे बड़ा घरेलू इवेंट है और 11 जनवरी से शुरू होने वाली भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले खिलाड़ियों के लिए अहम तैयारी मंच माना जा रहा है।

विराट कोहली का उदाहरण और मुंबई को उम्मीद

इस महीने की शुरुआत में विराट कोहली को दिल्ली की संभावित विजय हजारे टीम में शामिल किया गया था। इससे संकेत मिलता है कि रोहित शर्मा, जायसवाल और सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ी भी उपलब्धता के आधार पर अपनी-अपनी घरेलू टीमों के लिए खेल सकते हैं। अगर ये स्टार खिलाड़ी मुंबई के लिए उतरते हैं, तो टीम का विजय हजारे अभियान और भी मजबूत हो सकता है।

टी20 विश्वकप के लिए आज भारतीय टीम की घोषणा कर सकता है बीसीसीआई

मुम्बई । अगले साल की शुरुआत में होने वाले टी20 विश्वकप क्रिकेट के लिए शनिवार को भारतीय टीम की घोषणा हो सकती है। अब देखना होगा कि इसमें किन-किन खिलाड़ियों को अवसर मिलता है। भारतीय टीम नये साल की शुरुआत में जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी ही धरती पर 5 मैच की टी20 सीरीज खेलेगी। जिसके बाद फरवरी में टी20 विश्वकप कप शुरु होगा। आमतौर पर आईसीसी टूर्नामेंट के लिए टीमों को एक महीने पहले अपने दल घोषित करने होते है पर भारतीय बोर्ड अधिकतर अंतिम समय में ही टीम की घोषणा करता रहा है हालांकि इस बार माना जा रहा है कि बोर्ड टीम की घोषणा पहले ही कर सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई 20 दिसंबर को ही न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के साथ-साथ ही विश्वकप के लिए भी टीम की घोषणा कर सकता है। भारत की 15 सदस्यीय टी20 टीम और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीमों के चयन की बैठक शनिवार 20 दिसंबर को दोपहर होने की संभावना है। अब देखना होगा कि इसमें चोटिल बल्लेबाज शुभमन गिल को टीम में जगह मिलती है या नहीं। शुभमन फिट नहीं होने के कारण ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज नहीं खेल पाये थे। शुभमन का प्रदर्शन इस साल टी20 में अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में अगर वह फिट नहीं होते हैं तो उनकी जगह पर संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को अंतिम ग्यारह में जगह मिल सकती है। वहीं पिछले काफी समय से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भी टीम में जगह मिलने की उम्मीद है।

होल्डर गुजरात टाइटंस के लिए फायदेमंद साबित होंगे : पार्थिव

नई दिल्ली। गुजरात टाइटंस ने इस बार आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर को सबसे अधिक 7 करोड़ रुपए में खरीदने को सही फैसला बताया है। टीम के सहायक कोच पार्थिव पटेल ने कहा है गुजरात टाइटंस की पिछले काफी समय से होल्डर पर नजरें थीं। पार्थिव ने कहा, हमने पिछले डेढ़ साल से होल्डर पर नजर बनाए रखी थी। वह टी20 क्रिकेट के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। उन्होंने सभी लीग में अच्छा खेला है। गुजरात टाइटंस हमेशा अनुभवी खिलाड़ियों को जोड़ने के लिए तैयार रहता है। हम सभी जानते हैं कि होल्डर कितने फायदेमंद हैं, वह अच्छी बल्लबाजी और गेंदबाजी करते हैं। वहीं युवा अशोक शर्मा को 90 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ने पर पार्थिव पटेल ने कहा, हम सभी को लगता है कि अशोक अच्छी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। हम टीम में एक प्रतिभाशाली अनकैप्ड तेज गेंदबाज को लाना चाहते थे और ये खोज अशोक के साथ पूरी हुई है। वहीं फ्रेंचाइजी ने पृथ्वीराज यारा को 30 लाख रुपए में खरीदने के फैसले का भी बचाव किया है। इस युवा की प्रशंसा करते हुए कोच ने कहा, वह काफी समय से फर्स्ट-क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। बीच में उन्हें चोट भी लगी थी। वह हमारे लिए एक बाएं हाथ के गेंदबाज के तौर पर विविधता लाते हैं। हमें लगा कि पृथ्वीराज और अशोक का का संयोजन अच्छा रहेगा। हम उन्हें अपनी टीम में लाकर खुश हैं।

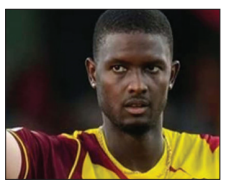

गुजरात टाइटंस टीम : रिटेंशन : अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बराड़, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, साई किशोर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, जयंत यादव, जोस बटलर, कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुभमन गिल और वाशिंगटन सुंदर।

नीलामी में खरीदारी : जेसन होल्डर (7 करोड़ रुपए), टॉम बैंटन (2 करोड़ रुपए), अशोक शर्मा (90 लाख रुपए), ल्यूक वुड (75 लाख रुपए) और पृथ्वी राज (30 लाख रुपए)।

गौतम गंभीर को लेकर कपिल देव का दो टूक: वो कोच नहीं, टीम संभालने वाले मैनेजर हैं!

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिग्गज ऑलराउंडर और भारत के पहले विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव ने आधुनिक कोच की परिभाषा पर ही सवाल उठाकर एक नई बहस छेड़ दी है। भारत के मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर पर उनकी तीखी टिप्पणियों ने दक्षिण अफ्रीका में भारत की हालिया टेस्ट सीरीज हार के बाद पहले से ही चल रही तीखी बहस को और हवा दे दी है। गंभीर की कोचिंग में भारत ने अब तक खेले गए 19 टेस्ट मैचों में से सात जीते हैं, दस हारे हैं और दो ड्रॉ रहे हैं। इनमें न्यूजीलैंड (0-3) और दक्षिण अफ्रीका (0-2) के खिलाफ घरेलू मैदान पर क्लीन स्वीप भी शामिल है।

टीम ने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी भी 1-3 से गंवाई। गंभीर के कार्यकाल में एकमात्र टेस्ट सीरीज जीत बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू मैदान पर मिली हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में घरेलू मैदान पर हुई टेस्ट सीरीज में करारी हार के बाद गंभीर को बर्खास्त करने की मांग तेज हो गई है, प्रशंसक और विशेषज्ञ उनकी टीम चयन और रणनीति की आलोचना कर रहे हैं। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के आईसीसी शताब्दी सत्र में बोलते हुए कपिल देव ने स्पष्ट किया कि समकालीन क्रिकेट में ÷कोच÷ शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है।

उनके अनुसार, आज के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पारंपरिक अर्थों में कोच की नहीं, बल्कि एक कुशल प्रबंधक की आवश्यकता है। कपिल ने साफ तौर पर कहा कि गौतम गंभीर कोच नहीं हो सकते, लेकिन टीम के प्रबंधक के रूप में वे निश्चित रूप से भूमिका निभा सकते हैं। उनका तर्क खेल के विकास पर आधारित था। लेग स्पिनरों से लेकर विकेटकीपरों और तेज गेंदबाजों तक, हर खिलाड़ी की विशेषज्ञता को देखते हुए, कपिल ने सवाल उठाया कि एक व्यक्ति सभी को तकनीकी रूप से कैसे प्रशिक्षित कर सकता है। इसके बजाय, उन्होंने जोर दिया कि खिलाड़ियों के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और अपेक्षाओं का प्रबंधन करना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन गई है।

कपिल देव की ये टिप्पणियां भारतीय क्रिकेट के लिए एक संवेदनशील समय पर आई हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 0-2 की हार के बाद गौतम गंभीर आलोचनाओं के घेरे में हैं। आलोचकों ने उनके खेलने के तरीके पर सवाल उठाए हैं, खासकर खिलाड़ियों को लगातार बदलने और अंशकालिक खिलाड़ियों पर निर्भरता पर, जिससे कई लोगों का मानना है कि टीम का संतुलन बिगड़ गया। कपिल ने रणनीति की सीधी आलोचना करने के बजाय व्यापक परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि गंभीर की ताकत तकनीकी कोचिंग के बजाय खिलाड़ियों को बेहतर ढंग से संभालने में है, इस तरह उन्होंने पूर्व सलामी बल्लेबाज का परोक्ष रूप से बचाव करते हुए उनकी भूमिका से जुड़ी अपेक्षाओं को नए सिरे से परिभाषित किया।

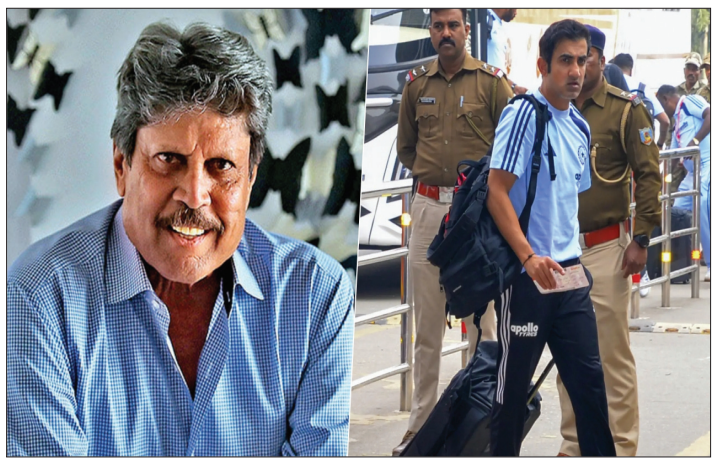

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

'रूस अगले साल भी युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहा', यूक्रेनी राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों से लगाई मदद

कीव, एजेंसी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस अगले साल भी युद्ध जारी रखने की तैयारी कर रहे हैं। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका से मदद देने की अपील की। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा, 'आज हमें फिर से ऐसे संकेत मिले हैं कि मॉस्को अगले साल भी लड़ाई जारी रखने की तैयारी कर रहा है। ये संकेत सिर्फ हमारे लिए नहीं हैं बल्कि ये हमारे सहयोगी देशों के लिए भी संकेत हैं कि वे भी इसे देखें और न सिर्फ देखें बल्कि इस पर प्रतिक्रिया भी दें। खासकर अमेरिका, जो अक्सर कहता है कि रूस इस युद्ध को खत्म करना चाहता है।' जेलेंस्की ने आगे लिखा, 'अमेरिका दावा करता है कि रूस, युद्ध रोकना चाहता है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, वे बिल्कुल उलट हैं। रूस की मानसिकता को समझकर उसके हिसाब से कार्रवाई की जानी चाहिए। रूस कूटनीति को अहमियत नहीं देता और वह बस यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों को तबाह करना चाहता है। वह यूक्रेन की जमीन को चुराकर उसे कानूनी वैधता देना चाहता है। यूक्रेन के बाद रूस यूरोप का रुख करेगा, जहां वह यूरोप की जमीन को भी ऐतिहासिक रूप से रूस की जमीन बताएगा।' जेलेंस्की ने इसके बाद लिखा कि यूक्रेन अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद की जरूरत है। साथ ही रूस की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई और राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी जरूरत है।

इस्राइल ने गाजा के रिहायशी इलाके में दागे मोर्टार, 10 लोग घायल

येरूशलम, एजेंसी। इस्राइल की सेना ने बुधवार को गाजा पट्टी के एक फलस्तीनी रिहायशी इलाके में मोर्टार गोला दागा। इस घटना में कम से कम 10 लोगों के घायल होने की पुष्टि स्वास्थ्य अधिकारियों ने की है। इस्राइली सेना ने कहा कि यह फायरिंग संघर्षविराम समझौते में तय की गई तथाकथित 'येलो लाइन' के पास एक सैन्य अभियान के दौरान हुई। सेना के मुताबिक मोर्टार अपने तय लक्ष्य से भटक गया, हालांकि यह नहीं बताया गया कि लक्ष्य क्या था। सेना ने घटना की जांच शुरू कर दी है। गाजा सिटी के अल-अहली अस्पताल के निदेशक फादेल नईम ने बताया कि घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर से लागू संघर्षविराम के बाद यह पहली घटना नहीं है, जब येलो लाइन के बाहर इस्राइली फायरिंग से नागरिक हताहत हुए हों। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार संघर्षविराम के बाद अब तक इस्राइली कार्रवाई में 370 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस्राइल का कहना है कि उसने हमास की उल्लंघनों के जवाब में कार्रवाई की है, जबकि फलस्तीनी पक्ष का आरोप है कि लाइन के स्पष्ट रूप से चिन्हित न होने के कारण आम नागरिक निशाना बन रहे हैं।

रैपर के फ्लॉक को गोलीबारी मामलों में 30 साल की सजा

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी रैपर के फ्लॉक (केविन पेरेज) को ब्रॉन्क्स में 2020-21 के बीच हुई कई गोलीबारी घटनाओं में दोषी पाए जाने पर 30 साल की सजा सुनाई गई है। 22 वर्षीय रैपर पर चार अलग-अलग घटनाओं में कई लोगों को घायल करने और एक गैंग का मुखिया बनने का आरोप था। जज लुइस लिमन ने कहा कि पेरेज ने सोशल मीडिया पर हिंसा को बढ़ावा दिया और युवा प्रशंसकों को गलत संदेश दिया। मार्च में उन्हें रैकेटियरिंग साजिश और हत्या के प्रयास सहित कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

कोलंबिया में विद्रोहियों के हमले में दो पुलिस अफसरों की मौत

बोगोटा , एजेंसी। कोलंबिया के काली में नेशनल लिबरेशन आर्मी (ईएलएन) विद्रोहियों के हमले में दो पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। दोनों अधिकारी बाइक पर गश्त कर रहे थे, तभी सड़क किनारे लगाए बम से निशाना बनाया गया। घटना से पहले ईएलएन ने कैरेबियन में अमेरिकी सैन्य तैनाती के विरोध में 72 घंटे का आर्म्ड स्ट्राइक शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक, सप्ताहांत में पुलिस स्टेशन व सैन्य ठिकानों पर भी हमले हुए, जिनमें एक एंबुलेंस चालक की मौत हुई।

बक रॉजर्स स्टार गिल जेरार्ड का 82 साल की उम्र में कैंसर से निधन

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी अभिनेता गिल जेरार्ड का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 1979 की साइ-फाई सीरीज बक रॉजर्स इन 25 सेंचुरी में मुख्य भूमिका निभाई थी। जेरार्ड की पत्नी जेनेट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि जेरार्ड को कैंसर था। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उनके साथ बिताया गया समय मेरे लिए कभी पर्याप्त नहीं हो सकता।

भारत-अमेरिका के व्यापार संबंधों के लिए 2026 की पहली तिमाही होगी काफी अहम: रिचर्ड रोसो

वाशिंगटन , एजेंसी। भारत और अमेरिका के रिश्तों ने साल 2025 में कई उतार-चढ़ाव देखे। साल की शुरुआत में जहां दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर अच्छी तेजी दिखी, वहीं आगे चलकर व्यापार से जुड़े मतभेद और कुछ भू-राजनीतिक मुद्दों पर असहमति भी सामने आई। हालांकि अब हालात धीरे-धीरे स्थिर हो रहे हैं और दोनों देश 2026 को ज्यादा सकारात्मक और उत्पादक बनाने की दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यह बात अमेरिका में भारत मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ रिचर्ड रोसो ने एक साक्षात्कार में कही है। वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (सीएसआईएस) में भारत और उभरती एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर काम कर रहे रिचर्ड रोसो ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'यह रिश्ता साफ तौर पर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत उन देशों में शामिल था, जिन्होंने अमेरिका के साथ शुरुआत में ही बेहतर तरीके से संपर्क बनाया। इसमें राष्ट्राध्यक्ष स्तर की मुलाकात और क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जैसे अहम कदम शामिल थे। हालांकि, कुछ समय बाद मतभेद सामने आने लगे।

रोसो ने बताया कि भारत-पाकिस्तान तनाव को लेकर अलग-अलग नजरिया है और भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद जारी रखने पर

वॉशिंगटन में चिंता बढ़ी। इसके बावजूद रोसो का मानना है कि मौजूदा दौर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा शांत है। उन्होंने कहा, 'अब तक व्यापार समझौता पूरा नहीं हुआ है। रोज-रोज की तीखी बयानबाजी भी नहीं दिखती। यह माहौल 2026 में रिश्तों को ज्यादा मजबूत बनाने की नींव रख सकता है। व्यापार के मुद्दे पर रोसो ने माना कि भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण बाजार रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिनसे अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में निर्यात करना मुश्किल हुआ। ये नीतियां आज भी अमेरिका की सोच को प्रभावित करती हैं, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप के नजरिए से।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत की व्यापार नीति में समय के साथ बदलाव आया है। आयात शुल्क में कटौती, स्थानीय निर्माण की अनिवार्यता में कमी और ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ बड़े व्यापार समझौते इसके उदाहरण हैं। राजनीतिक स्तर पर आई डगमगाहट के बावजूद, व्यापारिक आंकड़े मजबूत बने हुए हैं। रोसो ने कहा कि आयात और निर्यात दोनों में साल-दर-साल बढ़ोतरी दिख रही है। 2025 के व्यापार आंकड़ों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर उच्च सिंगल-डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि, उन्होंने हाल के महीनों में भारतीय निर्यात में आई गिरावट की ओर भी इशारा किया। रोसो ने कृषि क्षेत्र को व्यापार समझौते में सबसे बड़ी अड़चन बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के बुनियादी कृषि उत्पादों तक पहुंच की मांग कर रहे हैं। यह भारत के लिए संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि देश में बड़ी संख्या में किसान हैं, जिनके पास वैकल्पिक रोजगार के सीमित अवसर हैं। ऐसे में बड़े स्तर पर उदारीकरण सामाजिक और राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। भारत के पक्ष का समर्थन करते हुए रोसो ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था असमान है। जहां एक ओर सेवा क्षेत्र काफी उत्पादक है, वहीं कृषि क्षेत्र की उत्पादकता कम है। उन्होंने कहा कि सुधार धीरे-धीरे और संतुलित तरीके से होने चाहिए ताकि लोगों की जिंदगी पर अचानक नकारात्मक असर न पड़े। निवेश के मोर्चे पर रोसो ने भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में अमेरिका की अरबों डॉलर की प्रतिबद्धताओं को दीर्घकालिक सोच का संकेत बताया। उन्होंने कहा कि भविष्य में दुनिया की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी और भारत उनमें से एक होगा। उनके अनुमान के मुताबिक, भारत मध्य सदी तक 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है और अमेरिका व चीन को सीधी चुनौती देगा।

सुधारों की बात करें तो रोसो ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत धीमी रही, लेकिन हाल के महीनों में रफ्तार बढ़ी है। उन्होंने जीएसटी में बदलाव और बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति जैसे कदमों का जिक्र किया।

2026 की शुरुआत को लेकर रोसो ने कहा कि साल की पहली तिमाही बेहद अहम होगी। संभावित व्यापार समझौता, अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा, क्वाड नेताओं की बैठक और फरवरी में होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट इस दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं। साथ ही, भारत में होने वाले राज्य चुनाव भी सुधारों की गति को प्रभावित करेंगे। रोसो ने कहा कि पिछले 11 से 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा के मोर्चे पर खुद को काफी मजबूत किया है और अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग भी गहरा हुआ है।

इमरान खान की बहनों और समर्थकों को प्रदर्शन करना पड़ा भारी, आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान पुलिस ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहनों और उनके दर्जनों समर्थकों के खिलाफ अडियाला जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। इमरान खान की बहनों और उनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जेल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। दरअसल, अधिकारियों ने जेल में बंद नेता के रिश्तेदारों और वकीलों को उनसे मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस के अनुसार, खान की दो बहनों अलीमा खान और नोरीन नियाजी के साथ-साथ सलमान अकरम राजा, नईम पंजोथा, कासिम खान, आलिया हमजा, राजा नासिर अब्बास नाम के पार्टी के नेताओं और समर्थकों के खिलाफ रावलपिंडी के सदर बेरोनी पुलिस स्टेशन में आतंकवाद विरोधी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने कथित तौर पर राज्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 120 भी लगाई। पुलिस के मुताबिक कल रात मौके पर ही कम से कम 14 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था। एफआईआर में उल्लिखित अपराधों में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं। अगस्त 2023 से जेल में बंद इमरान खान के खिलाफ अप्रैल 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से कई मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने खान से मुलाकातों पर बिना पूर्व सूचना के प्रतिबंध लगा दिए हैं। पुलिस का कहना है कि इस बहाने से कि आगंतुक ऐसी मुलाकातों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। खान से आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का यातना मामलों की विशेषज्ञ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में स्थिति पर चिंता जताई और पाकिस्तान सरकार से कहा कि वह तत्काल और प्रभावी कदम उठाए।

चीन के सपने को अमेरिका का झटका, ताइवान को 10 अरब डॉलर के हथियार देने को मंजूरी

बीजिंग, एजेंसी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चीन को करारा झटका दिया है। सालों से दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर की स्थिति है और अब रणनीतिक मोर्चे पर अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया है कि चीन को मिर्ची लग सकती है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने उस ताइवान को 10 अरब डॉलर के हथियार बेचने को मंजूरी दी है, जिससे चीन का तनाव बना रहता है। चीन का ताइवान पर दावा रहा है, जबकि ताइवानी नेतृत्व का जोर स्वतंत्र देश पर है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन अकसर आमने-सामने आते रहे हैं। यही नहीं 2022 में अमेरिकी नेता नैन्सी पेलोसी भी ताइवान गई थीं और उस दौरान चीनी फाइटर जेट्स ने उनके विमानों का पीछा करने की कोशिश की थी। इससे काफी तनाव पैदा हो गया था। अमेरिका की ओर से मंजूरी किए गए पैकेज के तहत ताइवान को मध्यम दूरी की मिसाइलें दी जाएंगी। इसके अलावा होवित्जर तोपों और ड्रोन्स की भी बिक्री शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार देर रात इन हथियार सौदों की घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित संबोधन के दौरान की। अपने भाषण में ट्रंप ने विदेश नीति के मुद्दों का बहुत कम उल्लेख किया और चीन के साथ व्यापार या अन्य मसलों पर कोई बात नहीं की। इन आठ हथियार बिक्री समझौतों में 82 उच्च गतिशीलता वाली तोपखाना रॉकेट प्रणाली (हिमार्स) और 420 सैन्य सामरिक मिसाइल प्रणाली शामिल हैं। ये वही प्रणालियां हैं जैसी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के दौरान अमेरिका ने रूस के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए यूक्रेन को प्रदान की थीं। इनकी कुल कीमत चार अरब डॉलर से अधिक बताई गई है। इसके अलावा इस पैकेज में 60 स्वचालित होवित्जर प्रणालियां और उनसे जुड़े उपकरण भी शामिल हैं, जिनकी कीमत भी चार अरब डॉलर से अधिक है। साथ ही ड्रोन की बिक्री लगभग एक अरब डॉलर से अधिक मूल्य की बताई गई है। वहीं अन्य सौदों में एक अरब डॉलर से अधिक मूल्य का सैन्य सॉफ्टवेयर, 70 करोड़ डॉलर से अधिक के जैवेलिन और टीओडब्ल्यू मिसाइल, 9.6 करोड़ डॉलर के हेलीकॉप्टर के पुर्जे और हार्पून मिसाइलों के लिए 9.1 करोड़ डॉलर की नवीनीकरण किट शामिल हैं।

सुरक्षा उपायों के साथ चिकित्सीय आत्महत्या को मंजूरी, गवर्नर बोलीं- कुछ नियमों के साथ वैध बनाएंगे

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिकी राज्य न्यूयॉर्क में सुरक्षा उपायों के साथ चिकित्सीय आत्महत्या को मंजूरी मिलने जा रही है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होसुल ने बताया कि डॉक्टरों की देखरेख में गंभीर रूप से बीमार मरीजों को चिकित्सीय आत्महत्या करने को कानूनी वैधता देने पर सहमत बन गई है। अगले साल इस कानून पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।

अगले साल हस्ताक्षर के साथ बन जाएगा कानून : गवर्नर ने कहा, न्यूयॉर्क 'सुरक्षा उपायों' के साथ मेडिकल सहायता से आत्महत्या को कानूनी बनाने जा रहा है। बुधवार को गवर्नर और राज्य के कानूनी जानकारों के बीच हुए एक समझौते के तहत, न्यूयॉर्क गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए मेडिकल सहायता से आत्महत्या को कानूनी बनाने वाला राज्य बनने जा रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नर कैथी

होसुल ने बताया कि वह बिल में कई सुरक्षा उपायों को जोड़ने पर जोर देने के बाद अगले साल इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रही हैं। अमेरिका में करीब एक दर्जन राज्यों में मेडिकल सहायता से आत्महत्या की अनुमति देने वाले कानून हैं। हाल ही में इलिनोइस राज्य में भी हाल ही में ऐसा कानून बना है, जिस पर अगले साल हस्ताक्षर होंगे। न्यूयॉर्क के मेडिकल एड इन डाइंग एक्ट के लिए यह जरूरी है कि एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति, जिसके छह महीने के भीतर मरने की उम्मीद है, वह जीवन समाप्त करने वाली दवाओं के लिए लिखित अनुरोध करे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि रोगी पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है, दो गवाहों को अनुरोध पर हस्ताक्षर करने होंगे। इसके बाद अनुरोध को व्यक्ति के इलाज करने वाले डॉक्टर के साथ-साथ एक सलाहकार डॉक्टर द्वारा भी अनुमोदित किया जाना होगा।

कुछ प्रावधानों को जोड़ने पर बनी सहमति : गवर्नर ने कहा कि बिल के प्रायोजकों और कानूनी जानकारों ने ऐसे प्रावधान जोड़ने पर सहमति व्यक्त की है जिसमें एक मेडिकल डॉक्टर से पुष्टि की जरूरत होगी कि व्यक्ति के पास वास्तव में जीने के लिए छह महीने से कम समय बचा है, साथ ही एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से पुष्टि की जाएगी कि रोगी निर्णय लेने में सक्षम है और उस पर कोई दबाव नहीं है। बुधवार को होसुल ने कहा कि इस बिल को सपोर्ट करना गवर्नर के तौर पर उनके सबसे मुश्किल फैसलों में से एक था। उन्होंने कहा, 'मैं कौन होती हूं जो आपको या आपके किसी अपने को, जो ज़िंदगी के आखिरी समय में जिस चीज की मांग रहे हैं, उसे देने से मना करूं? मैं अब ऐसा और नहीं कर सकती थी।' यह कानून पहली बार साल 2016 में पेश किया गया था।

पुलित्जर विजेता पत्रकार पीटर अर्नेट का निधन, गोलियों और बमों के बीच दशकों तक की रिपोर्टिंग

लॉस एंजिलिस, एजेंसी। वियतनाम के धान के खेतों से लेकर इराक के रेगिस्तानों तक युद्धों की प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग दुनिया तक पहुंचाने वाले, गोलियों और बमों से बचते हुए दशकों तक काम करने वाले पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार पीटर अर्नेट का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एसोसिएटेड प्रेस के लिए वियतनाम युद्ध की रिपोर्टिंग पर 1966 में अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग का पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले अर्नेट का बुधवार को न्यूपोर्ट बीच में निधन हुआ। उनके बेटे एंड्रयू अर्नेट ने बताया कि उस समय वे दोस्तों और परिवार से घिरे हुए थे। उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके बेटे एंड्रयू अर्नेट ने

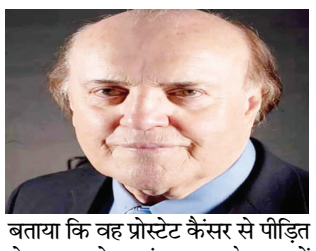

बताया कि वह प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे। वायर सेवा संवाददाता के रूप में अर्नेट 1962 से 1975 में युद्ध समाप्त होने तक वियतनाम में रिपोर्टिंग करते रहे और उस दौरान वे मुख्य रूप से अन्य पत्रकारों के बीच ही जाने जाते थे। हालांकि 1991 में सीएनएन के लिए पहले खाड़ी युद्ध की लाइव रिपोर्टिंग करने के बाद वे आम लोगों के बीच भी एक जाना-पहचाना नाम बन गए। एडिथ लेडरर 1972-73 में वियतनाम युद्ध के दौरान उनकी साथी व एसोसिएटेड प्रेस की संवाददाता थीं। उन्होंने कहा, पीटर अर्नेट अपने समय के युद्ध कवर करने वाले महान संवाददाताओं में से एक थे। वह निडर, साहसी और बेहतरीन लेखक थे। उनकी रिपोर्टिंग आने वाली पीढ़ियों के पत्रकारों और इतिहासकारों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। 1962 से 1975 तक अर्नेट वियतनाम में रिपोर्टिंग करते रहे। उन्होंने 1991 में पहले खाड़ी युद्ध के दौरान इराक से लाइव अपडेट देकर दुनियाभर में प्रसिद्धि हासिल की। अमेरिकी नेतृत्व वाले हमले से पहले अधिकांश पश्चिमी पत्रकार बगदाद छोड़ चुके थे, लेकिन अर्नेट वहीं रहे। मिसाइल हमलों के बीच उन्होंने अपने होटल से फोन से लाइव रिपोर्टिंग की। उन्होंने 1966 में अमेरिकी सैनिकों की बटालियन के साथ नॉर्थ वियतनामी स्नाइपरों के खिलाफ ऑपरेशन में भाग लिया। उन्होंने याद किया कि एक गोली बटालियन कमांडर को लगी, जो उनके सामने गिर गए। अर्नेट ने वियतनाम में काम करने से एक साल पहले एसोसिएटेड प्रेस में इंडोनेशिया के संवाददाता के रूप में अपनी नौकरी शुरू की थी। इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट करने के बाद उन्हें देश से निकाल दिया गया।

वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध पर अड़े ट्रंप, सैन्य कार्रवाई रोकने की अमेरिकी संसद की कोशिश भी बेकार

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी बढ़ा दी है, जिसके बाद वेनेजुएला ने अमेरिका पर युद्ध थोपने का आरोप लगाया। बुधवार को कुछ डेमोक्रट सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप की सैन्य कार्रवाई को रोकने की मांग की गई थी, लेकिन सदन के रिपब्लिकन सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, जिसके बाद यह खारिज हो गया। डेमोक्रेट्स के समर्थन वाला प्रस्ताव खारिज ट्रंप ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई बढ़ा दी हैं। जिस पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। अमेरिकी सेना कैसे एक अभियान चला रही है, जिसके तहत कैरेबियाई क्षेत्र में कथित तौर पर ड्रग्स ले जा रहे 26 जहाजों को निशाना बनाया गया है और बुधवार को हुए एक हमले सहित इन हमलों में कम से कम 99 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका ने वेनेजुएला की घेराबंदी कर दी है और अपने युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। डेमोक्रेट्स ने युद्ध शक्तियों के प्रस्तावों का इस्तेमाल करके वोटिंग करवाई। इस प्रस्ताव के तहत ट्रंप प्रशासन को वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस की अनुमति लेना जरूरी हो जाता। रिपब्लिकन सांसदों ने ट्रंप के अभियान का समर्थन किया हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट सांसद, ग्रेगरी मीक्स ने तर्क दिया कि वेनेजुएला के खिलाफ ट्रंप की आक्रामकता असल में इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति वेनेजुएला के तेल पर नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप के अभियान का लगातार समर्थन किया है। सीनेट के बहुमत दल के नेता जॉन थून ने बुधवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वे वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो मुझे निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। मादुरो ने आरोप लगाया, 'अमेरिका, वेनेजुएला में लक्ष्य सत्ता परिवर्तन करके एक कठपुतली सरकार थोपना चाहता है जो 47 घंटे भी नहीं टिकेगी, जो संविधान, संप्रभुता और सारी संपत्ति सौंप देगी। इससे वेनेजुएला एक उपनिवेश बन जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा।' वहीं मंगलवार को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'वेनेजुएला के आसपास सैन्य तैनाती तब तक बढ़ेगी जब तक वेनेजुएला अमेरिका को तेल, ज़मीन और अन्य संपत्ति जो उन्होंने पहले हमसे चुराई थी, वापस नहीं कर देता।

अमेरिकी सीनेटर ने भारत-चीन से आने वाली जेनेरिक दवाओं पर बढ़ती निर्भरता पर जताई चिंता

वाशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका के एक सीनेटर ने भारत और चीन समेत दूसरे देशों में बनी जेनेरिक दवाओं पर बढ़ती निर्भरता को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सीनेटर रिक स्कॉट का कहना है कि भारत और चीन से आने वाली जेनेरिक दवाएं पर बढ़ती निर्भरता अमेरिकी परिवारों के लिए खतरा बन सकती है। सीनेट की स्पेशल कमेटी ऑन एजिंग के अध्यक्ष सीनेटर रिक स्कॉट ने बुधवार (स्थानीय समय) को कहा कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं और उनके कच्चे रसायनों का बड़ा हिस्सा विदेशों में बनता है। यह स्थिति न सिर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्य बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। रिक स्कॉट ने कहा, 'जो भी अमेरिकी दूसरे देशों में बनी जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है, उसे अपनी दवाओं में छिपे इंग्रीडिएंट्स के बारे में जानने का हक है।' उनकी समिति अमेरिका की दवा आपूर्ति श्रृंखला में मौजूद कमजोरियों को उजागर करने के लिए एक बार फिर सक्रिय हुई है। सीनेटर स्कॉट इस मुद्दे पर समिति की वरिष्ठ सदस्य सीनेटर किर्स्टन गिलिब्रैंड के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके तहत कई जांच, सुनवाई और सरकारी एजेंसियों और उद्योग जगत के साथ संवाद किए गए हैं। सीनेटर स्कॉट के अनुसार, अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली जेनेरिक दवाओं में लगभग 80 प्रतिशत एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) विदेशों से आते हैं। इनमें से कई दवाएं असुरक्षित और गंदी फैक्ट्रियों में तैयार की जाती हैं, जहां निरीक्षण बहुत कम होता है। कुछ मामलों में इन दवाओं से गंभीर स्वास्थ्य नुकसान होता है। उन्होंने कहा, 'ये दवाएं लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता एक रणनीतिक कमजोरी भी है। 'स्कॉट ने चेतावनी दी कि चीन किसी भी समय दवाओं की आपूर्ति

रोक सकता है, जिससे बुजुर्गों, सेना के जवानों और आम अमेरिकियों को जरूरी दवाएं नहीं मिल पाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही विदेशी फैक्ट्रियों में कुछ अचानक निरीक्षण किए जा रहे हों, लेकिन अमेरिकी एफडीए अमेरिका के बाहर स्थित दवा इकाइयों की तुलना में देश के भीतर कहीं ज्यादा निरीक्षण करता है। कई बार विदेशी कंपनियों को नियमों के उल्लंघन पर भी छूट दे दी जाती है ताकि सप्लाई चेन बाधित न हो। समिति की एक जांच रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका में दवाओं का घरेलू उत्पादन तेजी से घटा है। वर्ष 2024 में अमेरिका ने अपनी जरूरत की सिर्फ 37 प्रतिशत दवाएं खुद बनाईं, जबकि 2002 में यह आंकड़ा 83 प्रतिशत था। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले 95 प्रतिशत आइबुप्रोफेन, 70 प्रतिशत पैरासिटामोल और 45 प्रतिशत से अधिक पेनिसिलिन चीन से आते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि दुनियाभर में एंटीबायोटिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाले लगभग 90 प्रतिशत एपीआई चीन में बनते हैं। वहीं, अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली शीर्ष 100 जेनेरिक दवाओं में से 83 प्रतिशत के एपीआई का कोई भी स्रोत अमेरिका में नहीं है। भारत की भूमिका भी इस आपूर्ति श्रृंखला में अहम है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग 50 प्रतिशत जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं, लेकिन भारतीय कंपनियां भी अपने लगभग 80 प्रतिशत एपीआई के लिए चीन पर निर्भर हैं। समिति ने 2025 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि भारत में बनी जेनेरिक दवाओं से जुड़े गंभीर दुष्प्रभाव अमेरिका में बनी समान दवाओं की तुलना में 54 प्रतिशत अधिक पाए गए। इन दुष्प्रभावों में स्थायी विकलांगता या मौत जैसे जोखिम शामिल हैं। सीनेटर स्कॉट ने कहा कि अमेरिकियों को अपनी दवाओं की सुरक्षा और उपलब्धता को लेकर 'जुआ खेलने' के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दवा प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए तत्काल सुधारों की मांग की। समिति की रिपोर्ट में कई सुझाव दिए गए हैं, जिनमें जरूरी दवाओं के लिए अमेरिकी निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने वाला फेडरल बायर मार्केट बनाना, दवा आपूर्ति श्रृंखला की मैपिंग, दवाओं के मूल देश की जानकारी अनिवार्य करना, व्यापारिक जांच जैसे सेक्शन 232 का इस्तेमाल, 'मेड इन अमेरिका' लेबल के दुरुपयोग को रोकना और अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना शामिल है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

हरियाणा में वंदे मातरम पर चर्चा से लेकर मुख्यमंत्री और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक

गुरग्राम (एजेंसी)। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन में वंदे मातरम पर चर्चा से लेकर मुख्यमंत्री और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सत्र के दौरान विधायक घनश्याम ने वंदे मातरम पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस विधायक ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर कहा कि पहाड़ों को उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है। इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधकर कहा कि आपने विभाजन के समय वंदे मातरम को काट दिया था। इस बयान के बाद सदन में जमकर नारेबाजी हुई और स्पीकर हरविंद्र कल्याण को सदन की कार्यवाही 30 मिनट (लंच तक) के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस द्वारा लाए अविश्वास प्रस्ताव पर चुटकी ली। उन्होंने ध्यान दिलाया कि नोटिस पर विपक्ष के नेता (भूपेंद्र सिंह हुड्डा) के हस्ताक्षर नहीं थे। कांग्रेस को हुड्डा पर यक़ीन नहीं, देश की जनता को कांग्रेस पर नहीं, पर सदन में विपक्ष चाहिए था, हम तो हुड्डा साहब ही चाहते थे, चाहे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाहे या न चाहे। हुड्डा साहब ही सही !इस बयान के बाद कांग्रेस विधायक वेल में आ गए और जोरदार हंगामा किया। हंगामे के दौरान जब मंत्री विज बोलना चाहते थे, तब स्पीकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर विज नाराज हो गए और स्पीकर से ही भिड़ गए। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा है।

दिल्ली से कई एयरलाइन की 27 उड़ानें और इंडिगो की 59 घरेलू उड़ानें रद्द

नई दिल्ली (एजेंसी)। घने कोहरे और उसकी वजह से दृश्यता कम होने के कारण गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर कई एयरलाइन की 27 उड़ानें रद्द कर दी गईं और कई के परिचालन में देरी हुई। आधिकारिक सूत्र ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बीच इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक उसने अपने घरेलू नेटवर्क में 59 उड़ानें रद्द कर दी हैं। सूत्र ने बताया कि घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 16 प्रस्थान और 11 आगमन से जुड़ी अब तक 27 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। यात्रियों के लिए जारी एक परामर्श में डायल ने कहा कि घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन वर्तमान में कैट (श्रेणी)-तीन की स्थितियों के अंतर्गत आता है। इस तरह की परिस्थितियों में परिचालन में देरी या व्यवधान हो सकता है। इंडिगो की वेबसाइट के मुताबिक एयरलाइन ने गुरुवार को 59 उड़ानें रद्द की थी और शुक्रवार के लिए 28 और उड़ानें रद्द कीं। हालांकि, इंडिगो ने इसका कोई कारण नहीं बताया।

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने की एक और गिरफ्तारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में 16 दिसंबर को एक और गिरफ्तारी की है। ईडी के रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने शुक्रवार को बताया कि गिरफ्तार सौम्या चौरसिया को रायपुर की एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया जहां से उसे तीन दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। ईडी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एसीबी-ईओडब्ल्यू द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी पर जांच शुरू की है। पुलिस की जांच से पता चला कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराधों के माध्यम से लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय उत्पन्न हुई। ईडी की जांच में पता चला कि सौम्या को लगभग 115.5 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त हुई थी। ईडी की जांच में डिजिटल रिकॉर्ड, जब्त सामग्री और लिखित बयानों के रूप में जुटाए गए सबूतों से यह साबित हुआ कि सौम्या शराब गिरोह की सक्रिय सहयोगी थी।डिजिटल साक्ष्य से पुष्टि हुई कि वह अनिल टूटेजा और चैतन्य बघेल सहित शराब गिरोह के प्रमुख सदस्यों के बीच केंद्रीय समन्वयकर्ता एवं मध्यस्थ की भूमिका निभा रही थी तथा अवैध धन के सृजन एवं धनशोधन में सुविधा प्रदान कर रही थी। बरामद चैट से यह भी पता चला कि वह गिरोह के प्रारंभिक संगठन में शामिल थी जिसमें अरुण पति त्रिपाठी और निरंजन दास को आबकारी विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने में सहायता करना भी शामिल था। इससे पहले ईडी ने संबंधित मामले में अनिल टूटेजा (पूर्व आईएएस); अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस), कवासी लखमा (छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री) और चैतन्य बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र) को गिरफ्तार किया गया है।

मध्य प्रदेश के साईं भक्तों ने साईं बाबा के चरणों में 20 लाख रुपये का सोने का मुकुट चढ़ाया

शिर्डी (एजेंसी)। देश और विदेश के करोड़ों भक्तों की श्रद्धा का स्थान शिरडी के साईं बाबा में अटूट आस्था है। साईं बाबा के चरणों में भक्त अपना आभार जताने के लिए अलग-अलग तरह के दान करते हैं। इसी भावना के साथ, मध्य प्रदेश के हरदासपुर के एक साईं भक्त तेज बहादुर सिंह ने साईं बाबा के चरणों में 20 लाख रुपये का सोने का मुकुट चढ़ाया है। मध्य प्रदेश के हरदासपुर के रहने वाले तेज बहादुर सिंह 2002 से शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। पिछले 24 सालों से साईं बाबा में उनकी अटूट आस्था है। तेज बहादुर सिंह ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में साईं बाबा से जो कुछ भी मांगा, वह सब मुझे मिला। 24 साल बाद, साईं बाबा की कृपा से मुझे एक बेटा हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बड़ी मुश्किलों का सामना किया। हालांकि, साईं बाबा ने मुझे हमेशा उन मुश्किलों से बाहर निकाला। तेज बहादुर सिंह, जो पहले बहुत मुश्किल हालात में रहे थे, ने कहा है कि आज उन्हें जो भी कामयाबी, खुशी, खुशहाली और सुकून मिला है, वह सब साईं बाबा की कृपा से है। तेज बहादुर सिंह ने कहा, आज मेरे पास जो कुछ भी है, वह साईं बाबा की कृपा से है। इसलिए मुझे साईं बाबा को कुछ देना है। इसी भावना से मैंने यह सोने का मुकुट चढ़ाया है। दरअसल साईं भक्त तेज बहादुर सिंह ने श्रद्धा के साथ साईं बाबा के चरणों में करीब 200 ग्राम वज़न का एक आकर्षक और खूबसूरती से सजा हुआ सोने का मुकुट चढ़ाया। इस कलात्मक सोने के मुकुट की कीमत करीब 20 लाख 16 हज़ार रुपये है। साईं बाबा के चरणों में सोने का मुकुट चढ़ाने के बाद, इसे साईं बाबा संस्थान के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे को सौंप दिया गया। इस मौके पर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे ने दरियादिल साईं भक्त तेज बहादुर सिंह को सम्मानित किया और उनकी आस्था और योगदान के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया।

यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग भविष्य के लिये तैयार सिविल सेवाओं के निर्माण की कुंजी हैं: राष्ट्रपति

हैदराबाद (एजेंसी)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को भारत के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए सिविल सेवा भर्ती प्रकिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और तकनीकी तैयारी पर अधिक जोर देने का आह्वान किया।

राष्ट्रपति ने यहां रामोजी फिल्म सिटी में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि एक ऐसे मंच में भाग लेना सौभाग्य की बात है जो देश भर से यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों के प्रमुखों को एक साथ लाता है।

राष्ट्रपति ने भारत में लोक सेवा आयोगों के लंबे और प्रतिष्ठित इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना एक अक्टूबर, 1926 को हुई थी और बाद में भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत संघीय और प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया। 26 जनवरी, 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के बाद, संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों ने अपनी वर्तमान संवैधानिक भूमिकाएँ ग्रहण कीं।

केन्द्रीय और राज्य लोक सेवा आयोगों के योगदान का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवा आयोगों ने सरकारी प्रशासन में समानता, निष्पक्षता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन संस्थानों के माध्यम से चयनित सिविल सेवाएँ भारत के आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता और प्रशासन के लिए बहुत अहम रही हैं, जिससे संघ लोक सेवा आयोग देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में से एक बन गया है।

श्रीमती मुर्मु ने इस बात पर जोर दिया कि कौशल की कमी को प्रशिक्षण के माध्यम से दूर किया जा सकता है, लेकिन सत्यनिष्ठा की कमी ऐसी चुनौतियाँ पैदा करती है जिन पर काबू पाना मुश्किल है तो ऐसे में भर्ती में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोगों को उम्मीदवारों के बीच नैतिक अभिविन्यास और संवेदनशीलता का आकलन करने के लिए बेहतर प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रह रहे और कमजोर वर्गों के प्रति। राष्ट्रपति ने भविष्य की चुनौतियों पर जोर देते हुए लोक सेवा आयोगों से उभरते तकनीकी मुद्दों का अनुमान लगाने, पारदर्शिता को मजबूत करने और भर्ती प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ाने का आह्वान किया । उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन सर्वोत्तम विधियों , विशेष रूप से प्रौद्योगिकी अपनाने, कानूनी ढांचे और प्रक्रिया सुधारों को साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है।

उन्होंने भारत के तेजी से आर्थिक विकास और आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की उसकी महत्वाकांक्षा का जिक्र करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग भविष्य के लिए तैयार ऐसी सिविल सेवा का पोषण करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देना जारी रखेंगे जो स्थिरता को रचनात्मकता के साथ और निरंतरता को आधुनिकीकरण के साथ जोड़ती है। श्रीमती मुर्मु ने संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों को उनके प्रयासों में लगातार सफलता मिलने की शुभकामनाएं दीं।

सीएम सरमा की धमकियों और डराने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता : गौरव गोगोई

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि असम के सीएम हिमंत विस्वा सरमा की धमकियों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री की धमकियों और डराने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें ऐसा करते रहने दीजिए। आजकल उनकी बातों से राज्य के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि सीएम सरमा की धमकियों की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। गोगोई ने कहा कि सीएम सरमा अगले चार महीने जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद उन्हें जनता के बीच ही रहना होगा। सीएम पिछले कुछ महीनों से गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगाते हुए लगातार हमले कर रहे हैं। कोलबर्न ब्रिटेन की नागरिक हैं। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने 10 सितंबर को सीएम सरमा को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सरमा ने पिछले सप्ताह कहा था कि यह मामला केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया जाएगा। सीएम सरमा ने यह भी कहा कि एसआईटी जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में आरोप-पत्र दाखिल कर चुकी है, अब हम गौरव गोगोई के मामले पर आगे बढ़ेंगे। गर्ग हत्याकांड में सीआईडी की विशेष जांच टीम द्वारा दाखिल आरोप-पत्र का जिक्र करते हुए गोगोई ने कहा कि राज्य के अनुभवी वकीलों की टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि यह आरोप-पत्र अत्यंत कमजोर है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आरोप-पत्र सीएम सरकार के करीबी सहयोगी श्यामकानु महंत को बचाने की रणनीति के तहत सोच-समझकर तैयार किया गया है। इसमें कई प्रमुख आरोपियों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं, जिन्हें किया जाना चाहिए था।

सीएम ममता ने 'कर्मश्री' योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़ा राजनीतिक और वैचारिक बयान देते हुए राज्य सरकार की रोजगार योजना कर्मश्री का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर शर्म महसूस होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के नाम को कल्याणकारी योजनाओं से हटाया जा रहा है। ममता बनर्जी का इशारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के नाम में किए गए कथित बदलावों की ओर था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'कर्मश्री' योजना के तहत राज्य में 75 से 100 दिनों तक रोजगार दिया जाता है और अब यह योजना महात्मा गांधी के नाम से जानी जाएगी। ममता बनर्जी ने भावुक अंदाज़ में कहा, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं। राष्ट्रपिता का नाम योजनाओं से हटाया जा रहा है। मैं किसी और को दोष नहीं देती, क्योंकि मैं इसी देश की नागरिक हूं। हम राष्ट्रपिता को भूलते जा रहे हैं, यह दुखद है। उन्होंने केंद्र सरकार पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि अगर केंद्र महात्मा गांधी को सम्मान नहीं देगा तो बंगाल देगा। ममता ने कहा, अगर आप महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करेंगे, तो हम करेंगे। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने महात्मा गांधी के साथ-साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, डॉ. भीमराव आंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और लाल-बाल-पाल का भी उल्लेख किया। उन्होंने बंगाल की समावेशी संस्कृति की बात करते हुए कहा कि राज्य हर समुदाय और हर विचारधारा का सम्मान करता है। देखा जाये तो यह बयान ऐसे समय आया है जब मनरेगा के नाम और पहचान को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस चल रही है और तृणमूल कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की इतिहास और प्रतीकों को बदलने की राजनीति बता रही है।

कर्नाटक में सिद्धारमैया गुट के 30 विधायकों का रात्रिभोज... सीएम बदलाव की अटकलें फिर तेज

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रही खींचतान और बदलाव की अटकलें फिर तेज हो गई हैं। बेलगावी में वरिष्ठ लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली द्वारा आयोजित एक रात्रिभोज में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का समर्थन करने वाले विधायक शामिल हुए। इस जमावड़े में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पुत्र और विधान परिषद सदस्य यतींद्र सिद्धारमैया तथा विधायक के एन राजन्ना सहित तीस से अधिक विधायक शामिल हुए। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया स्वास्थ्य कारणों से कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जारकीहोली ने बैठक को राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान एक सामान्य सामाजिक मेलजोल बताया है लेकिन इसमें शामिल कई विधायकों ने संकेत दिया कि वहां राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के करीबी राजन्ना ने पुष्टि की कि पार्टी की रणनीति और नेतृत्व से जुड़े मामले बातचीत का हिस्सा थे। उन्होंने बताया कि इस तरह की बैठकें केवल सामाजिक मेलजोल के अलावा कई अन्य उद्देश्यों को भी पूरा करती हैं। यह रात्रिभोज उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के इसी तरह के एक कार्यक्रम की मेजबानी किए जाने के एक सप्ताह बाद हुआ है। इससे कर्नाटक कांग्रेस के भीतर स्पष्ट गुटबाजी और अलग अलग ध्रुवों का साफ पता लगाता है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के 20 नवंबर को अपना ढाई साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं ने जोर पकड़ लिया है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच साल 2023 के सत्ता साझाकरण समझौते की खबरें लगातार चर्चा में हैं हालांकि पार्टी आलाकमान के निर्देश पर दोनों नेताओं ने हाल ही में एक दूसरे के आवास पर मुलाकात की है। इससे फिलहाल श्री सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने और नेतृत्व की खींचतान में अस्थायी विराम का संकेत मिलता है।

वहीं विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सीएम सिद्धारमैया को विदा होने वाला मुख्यमंत्री कहने पर यतींद्र ने कहा कि ऐसी आलोचनाएं लंबे समय से चल रही हैं और इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सत्र के दौरान ऐसी बैठकें सामान्य होती हैं लेकिन ये पार्टी विधायकों के भीतर आंतरिक समीकरणों और निष्ठाओं को जरूर प्रदर्शित करती हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का शिकंजा : युवराज, सोनू सूद, उर्वशी की करोड़ों की संपत्ति अटैच

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑनलाइन सट्टेबाजी 1×बेट ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटिज की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली है। 1×बेट मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने नए प्रोविजनल अटैचमेंट किए हैं, जिन लोगों की संपत्तियां अटैच की गई हैं, उनमें युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हाजरा और नेहा शर्मा के नाम शामिल हैं। यह जांच कथित अवैध बेटिंग ऐप्स से जुड़ी है, जिन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की है या बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की है। कंपनी का दावा है कि 1×बेट एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त बुकी है, जो पिछले 18 सालों से बेटिंग इंडस्ट्री में है।

वायु प्रदूषण पर चर्चा से भागी सरकार... ये शीतकालीन नहीं, बल्कि प्रदूषण सत्र

-कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का केंद्र पर आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला कर आरोप लगाया कि हाल ही में समाप्त हुआ संसद का शीतकालीन सत्र सरकार की इस मुद्दे पर बहस करने की अनिच्छा के कारण प्रभावी रूप से प्रदूषण सत्र में बदल गया। प्रेसवार्ता को संबोधित कर कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि संसद में केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया से उन्हें गहरा सदमा लगा, जिसमें उन्होंने प्रदूषण और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के बीच किसी भी संबंध से इंकार किया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह शीतकालीन सत्र नहीं, बल्कि प्रदूषण सत्र था। मैं तब स्तब्ध रह गया जब सरकार ने गुरुवार को संसद में यह जवाब दिया कि प्रदूषण और फेफड़ों की समस्याओं के बीच कोई संबंध नहीं है। रमेश ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश भर में, विशेष रूप से उत्तर भारत में, जहां प्रदूषण का स्तर हफ्तों से गंभीर बना हुआ है, बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर विस्तृत चर्चा की बार-बार मांग की थी।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी। हम लोकसभा और राज्यसभा में वायु प्रदूषण पर बहस चाहते थे। कांग्रेस नेता ने केंद्र के उस दावे को खारिज किया कि विपक्ष द्वारा व्यवधान डालने से प्रदूषण पर बहस नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि विपक्ष की मांगों के बावजूद लोकसभा को इस मुद्दे पर चर्चा किए बिना अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। दुर्भाग्य से, लोकसभा में ही सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की गई।

केंद्र के आरोपों पर कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि चर्चा न होने की जिम्मेदारी सरकार की है। 'सरकार का यह बयान कि कांग्रेस के कारण प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी, गलत है। मैं इस बयान को पूरी तरह से खारिज करता हूं। रमेश की ये टिप्पणी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा कांग्रेस पर संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वायु प्रदूषण पर प्रस्तावित चर्चा को बाधित करने का आरोप लगाने के बाद आई है। रिजिजू ने दावा किया था कि सरकार पूरे दिन की बहस के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष के व्यवधान के कारण ऐसा करने से रोक दिया गया।

संसद में सवाल के बदले नकदी मामले में महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत

-हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश किया रद्द

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद में सवाल पूछने के बदले नकदी लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भारत के लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। अदालत के इस फैसले को मोइत्रा के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर शामिल थे, ने महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। महुआ मोइत्रा ने लोकपाल के 12 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ जांच और आगे की कार्रवाई की अनुमति दी गई थी।

सुनवाई के दौरान महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने दलील दी कि लोकपाल ने लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उनका कहना था कि अधिनियम की धारा 20(7) के तहत लोकपाल को किसी भी लोकसेवक के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसका पक्ष जानना अनिवार्य है। हालांकि महुआ मोइत्रा से लिखित जवाब मांगा गया था, लेकिन उनके अनुसार लोकपाल ने उनके जवाबों पर समुचित विचार किए बिना ही सीबीआई को आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दे दी।

मामले की पृष्ठभूमि में आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। दुबे का दावा था कि ये आरोप उन्हें वकील जयअनंत देहादराई से प्राप्त सबूतों के आधार पर लगे हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनियों के हित में संसद में सवाल उठाए।

भाजपा सांसद का यह भी दावा था कि महुआ मोइत्रा द्वारा पूछे गए 61 सवालों में से करीब 50 सवाल सीधे तौर पर हीरानंदानी समूह को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से थे। दूसरी ओर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने लोकपाल के आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि आरोपी को मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है और महुआ मोइत्रा को लिखित टिप्पणी देने का पूरा अवसर दिया गया था। हाईकोर्ट के ताजा फैसले से फिलहाल महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर विराम लग गया है।

दूसरे धर्म में लड़की ने की शादी पिता ने किया संपत्ति से बेदखल, कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को लेकर एक अहम फैसला दिया है। उसने टेस्टेटर की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए एक पिता की वसीयत को वैध ठहराया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी शैला जोसेफ को समुदाय से बाहर के लड़के से शादी करने के कारण संपत्ति से वंचित कर दिया था। यह मामला लैंगिक समानता के कई ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद वसीयत की स्वतंत्रता को अहमियत देता है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने केरल हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को पलट दिया, जिन्होंने वसीयत को दरकिनार करते हुए एनएस श्रीधरन की संपत्ति को नौ बच्चों में बराबर बांटने का आदेश दिया था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीधरन के नौ बच्चे थे, लेकिन 1988 में बनाई गई उनकी रजिस्टर्ड वसीयत में शैला को छोड़कर बाकी आठ बच्चों को संपत्ति सौंप दी गई थी। वजह थी शैला का समुदाय से बाहर शादी करना। जजमेंट लिखते हुए जस्टिस चंद्रन ने कहा कि वसीयत स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले रद्द किए जाते हैं। शैला जोसेफ का अपने पिता की संपत्ति पर कोई दावा नहीं है, क्योंकि वसीयत से यह संपत्ति अन्य भाई-बहनों को सौंप दी गई है।

कोर्ट में शैला की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी कृष्णन ने तर्क दिया कि उनकी क्लाइंट को कम से कम 1/9 हिस्सा मिलना चाहिए, जो संपत्ति का नगण्य हिस्सा है, लेकिन बेंच ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के बंटवारे में व्यक्ति की इच्छा के मामले में समानता का सवाल उठता ही नहीं। हम इक्विटी पर नहीं हैं। टेस्टेटर की इच्छा सर्वोपरि है। उसकी अंतिम वसीयत से विचलन या उसे निरस्त नहीं किया जा सकता।

बेंच ने टिप्पणी की कि वंचित करने की वजह बताई गई है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता हमारे लिए सावधानी का नियम नहीं तय करती। हम टेस्टेटर की जगह खुद को नहीं रख सकते। हम अपनी राय थोप नहीं सकते, उनकी इच्छा उनकी अपनी वजहों से प्रेरित है। फैसले में सिविल अपीलों को मंजूर करते हुए शैला की पार्टिशन सूट को खारिज कर दिया। मामला केरल का है, जहां श्रीधरन की मौत के बाद 1990 में भाई-बहनों ने इंजेक्शन सूट दाखिल किया था और वसीयत की कॉपी पेश की थी। शैला ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसे कोर्ट ने बाद में उनके खिलाफ माना